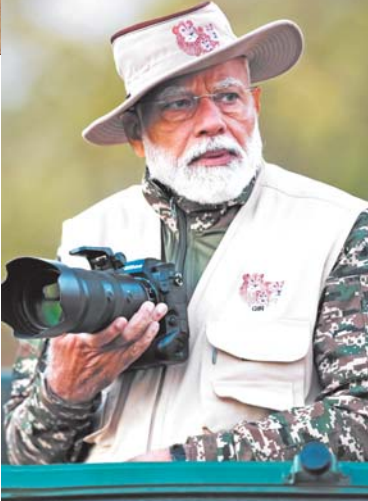


पीएम मोदी ने उठाया गिर नेशनल पार्क का लुत्फ

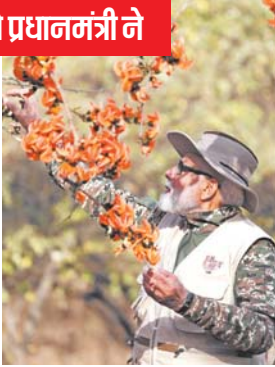
हाथ में कैमरा था और सामने शेर

जूनागढ़। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने विश्व वन्यजीव दिवस के अवसर पर सोमवार सुबह गुजरात के जूनागढ़ जिले में गिर वन्यजीव अभयारण्य में जंगल सफारी का आनंद लिया। वह सिर पर हेट और हाथ में कैमरे के साथ नजर आए। सोमनाथ से आने के बाद मोदी ने सासण में वन अतिथि गृह 'सिंह सदन' में रात्रि विश्राम किया। रविवार शाम को उन्होंने सोमनाथ मंदिर में भगवान शिव की पूजा अर्चना की थी। यह 12 ज्योतिर्लिंगों में से सबसे पहला ज्योतिर्लिंग है। 'सिंह सदन' से प्रधानमंत्री जंगल सफारी पर गए, उनके साथ कुछ मंत्री और वन विभाग के वरिष्ठ अधिकारी भी थे। पीएम मोदी शेरों की तस्वीरें उतारते नजर आए। गिर वन्यजीव अभयारण्य के मुख्यालय सासण गिर में प्रधानमंत्री, राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड (एनबीडब्ल्यूएल) की सातवीं बैठक की अध्यक्षता भी करेंगे।



पलाश के फूल चुने प्रधानमंत्री ने

बसंत के मौसम में जंगलों में पलाश के फूल भी खिले हुए हैं। पीएम मोदी जीप पर बैठे-बैठे ही फूल भी चुनने लगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पर भी लोगों से वन्य जीवों के संरक्षण और विविधता को बचाए रखने की अपील की।

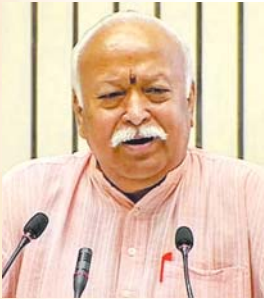


धूप का लुत्फ ले रहे थे शेर

नेशनल पार्क में शेर भी धूप का लुत्फ उठाते हुए दिखे। केंद्र सरकार ने एशियाई शेरों के संरक्षण के लिए 'ग्रेजुवेट लॉयन' के तहत 2,900 करोड़ रुपये से अधिक की राशि मंजूर की है। इन शेरों का एकमात्र निवास स्थान गुजरात है। एशियाई शेर गुजरात के नौ जिलों के 53 तालुकाओं में लगभग 30,000 वर्ग किलोमीटर में निवास करते हैं। इसके अलावा, एक राष्ट्रीय परियोजना के तहत जूनागढ़ जिले के न्यू पिपल्या में 20.24 हेक्टेयर से अधिक भूमि पर वन्यजीवों के चिकित्सीय निदान एवं रोग से बचाव के लिए एक 'राष्ट्रीय रेफरल केंद्र' स्थापित किया जा रहा है। संरक्षण प्रयासों को मजबूत करने के वास्ते सासण में वन्यजीव निगरानी के लिए उच्च तकनीक से युक्त निगरानी केंद्र और एक अत्याधुनिक अस्पताल भी स्थापित किया गया है। मोदी ने रविवार को रिलायंस जामनगर रिफाइनरी परिसर में स्थित पशु बचाव, संरक्षण और पुनर्वास केंद्र 'वनतारा' का भी दौरा किया।

सांध्यप्रकाश विशेष

मोहन भागवत कल आएंगे भोपाल, विद्या भारती के अभ्यास वर्ग का करेंगे उद्घाटन



भोपाल। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के प्रमुख मोहन भागवत 4 मार्च को भोपाल में विद्या भारती अखिल भारतीय शिक्षा संस्थान के लगभग 700 कार्यक्रमियों के लिए प्रशिक्षण शिविर का औपचारिक उद्घाटन करेंगे। यह प्रशिक्षण शिविर 3 से 8 मार्च तक शारदा विहार स्थित सरस्वती विद्या मंदिर आवासीय विद्यालय में होगा। देशभर से 700 से अधिक पूर्णकालिक कार्यकर्ता इस वर्ग में हिस्सा लेंगे। विद्या भारती के अखिल भारतीय अध्यक्ष दुसि रामकृष्ण राव ने बताया की एक प्रदर्शनी भी है, यह प्रदर्शनी भारत के गौरवशाली अतीत और उज्ज्वल भविष्य की झलक पेश करेगी। इसमें विद्या भारती का राष्ट्रीय योगदान, सैनिक स्कूल, कोविड-19 सेवा कार्य, रानी दुर्गावती की वीरगाथा, माता अहिंसाबाई होलकर का लोकसेवा योगदान और मध्य प्रदेश की धार्मिक-सांस्कृतिक धरोहर जैसे विषय शामिल होंगे।

सीएम रेखा गुप्ता ने लोगों से मांगे सुझाव, कहा- चुनावी वादों को पूरा करने का करेंगे प्रयास



नई दिल्ली। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सोमवार को घोषणा की कि सरकार 24 से 26 मार्च के बीच दिल्ली का बजट पेश करने की योजना बना रही है। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि बजट विकसित दिल्ली के विजन को दर्शाएगा, जिसमें समाज के सभी वर्गों के सुझाव शामिल होंगे। मुख्यमंत्री ने कहा, यह बजट विकसित दिल्ली बजट है और हम लोगों के सभी सुझावों को शामिल करने और अपने घोषणापत्र में किए गए सभी वादों को पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं जैसे महिलाओं को 2500 रुपए महीने की वित्तीय सहायता, प्रदूषण पर नियंत्रण, गरीबों को सस्ता और अच्छा खाना, बुजुर्गों को स्वास्थ्य सुविधा, यमुना नदी की सफाई और बहुत कुछ। सीएम गुप्ता ने कहा, महिला सम्मान योजना समेत भाजपा द्वारा किए गए सभी वादों को बजट में शामिल किया गया है। उन्होंने कहा कि 5 मार्च को सभी महिला संगठनों को संवाद के लिए विधानसभा में आमंत्रित किया गया है, ताकि वे बजट पर अपने सुझाव दे सकें। साथ ही बजट पर लोगों से सुझाव के लिए व्हाट्सएप नंबर जारी किया गया है।

अनोरा ने जीता ऑस्कर, बेस्ट एक्ट्रेस बनीं मिर्का मैडिसन, अनुजा की हार से भारत को झटका

लॉस एंजिल्स। दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित 97वें एकेडमी अवॉर्ड्स यानी ऑस्कर 2025 शुरू हो गया है। अवॉर्ड का आयोजन 2 मार्च 2025 को लॉस एंजिल्स के डॉल्बी थिएटर में किया गया, जिसका भारत में टेलीकास्ट 3 मार्च को सुबह 5.30 बजे से हुआ। अनोरा ने एक बार



फिर बेस्ट पिक्चर कैटेगोरी में ऑस्कर अवॉर्ड अपने नाम कर लिया है। चार अन्य कैटेगोरीज में भी 'अनोरा' ने ऑस्कर अवॉर्ड जीता है। माइकी मैडिसन बेस्ट एक्ट्रेस बनीं हैं। 2007 में आई फिल्म 'द डिपार्टेड' के बाद बेस्ट पिक्चर की कैटेगोरी में ऑस्कर जीतने वाली ये पहली 18+ रेटेड फिल्म है। 18+ का मतलब है वो फिल्म जिसे 18 साल या उससे ज्यादा उम्र वाले लोग ही देख सकते हैं।

ये हैं बेस्ट:- फिल्म- अनोरा, एक्ट्रेस- माइकी मैडिसन (अनोरा), एक्टर- एंड्रयू स्कोफील्ड (द ब्रेटलस्ट), एडिटर- जॉन डायरेक्टर- सीन बेकर (अनोरा), कॉस्ट्यूम- पॉल टाजवेल (इस कैटेगोरी में पहली बार एक ब्लैक को ऑस्कर अवॉर्ड मिला है।), एनिमेटेड शॉर्ट फिल्म- ह्यूमन मोलायमी और शिरिन सोहानी (द शैडो ऑफ़ द साइप्रस), एनिमेशन- लैटिवियाई, एक्टर (सपोर्टिंग रोल)- कीरन काल्किन (ए रियल पेन), एक्ट्रेस (सपोर्टिंग रोल)- जो सलदाना (एफिलिया पेरेज), सिनेमेटोग्राफी- द ब्लूलिस्ट, बेस्ट इंटरनैशनल शिरिन सोहानी (द शैडो ऑफ़ द साइप्रस), एनिमेशन- लैटिवियाई, एक्टर (सपोर्टिंग रोल)- कीरन काल्किन (ए रियल पेन), एक्ट्रेस (सपोर्टिंग रोल)- जो सलदाना (एफिलिया पेरेज), सिनेमेटोग्राफी- द ब्लूलिस्ट, बेस्ट इंटरनैशनल

फीचर फिल्म- आई एम रिटल हियर (ब्राजील), एडिटेड स्क्रॉनप्ले- कॉन्क्लेव, डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट- द ओनली गल इन द ऑर्केस्ट्रा, डॉक्यूमेंट्री फीचर फिल्म- नो अंदर लैंड, ऑरिजिनल सोनो- इंडाईएमएआई (एफिलिया पेरेज), ऑरिजिनल स्कोर- द ब्लूलिस्ट, मेकअप और हेयरस्टाइलिंग- द सन्सेट्स, कॉस्ट्यूम डिजाइन- विल्केड, साउंड- ड्यून 2, प्रोडक्शन डिजाइन- विल्केड, विजुअल इफेक्ट्स- ड्यून 2 है।

बच्चे सुरक्षित हैं और भारत का भविष्य भी सुरक्षित है: यादव

शिक्षा का अधिकार अधिनियम, पॉक्सो एक्ट और किशोर न्याय अधिनियम पर कार्यशाला का शुभारंभ

भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने आज शिक्षा का अधिकार अधिनियम, पॉक्सो एक्ट और किशोर न्याय अधिनियम के संबंध में जागरूकता पर राज्य स्तरीय कार्यशाला का कुशाभाव ठाकरे सभागार में दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ किया। कार्यशाला का आयोजन मध्य



प्रदेश बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा किया जा रहा है।

मुख्यमंत्री डा. यादव ने इस मौके पर कहा कि प्रदेश में पिछले एक साल में बच्चों के प्रति होने वाले अपराधों में कमी आई है, इस बात का हमें संतोष है। लेकिन बच्चों और महिलाओं के अपराधों में वृद्धि चिंताजनक है।



मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने कुबेश्वर धाम सीहोर में आयोजित रुद्राक्ष महोत्सव में पंडित प्रदीप मिश्रा का आशीर्वाद लिया।



हमारे पास इसका बहुत बड़ा दायरा है। यदि किशोर और बालिकाएं सुरक्षित हैं तो हमारे भारत का भविष्य सुरक्षित है। भगवान श्रीराम का वो दुश्मन याद करें, जब विश्वामित्र राजा दशरथ के यहां राक्षसों को मारने के लिए राम और लक्ष्मण को मांगने गये थे। वो चाहते तो सेना भी मांग सकते थे। लेकिन वो बच्चों को मांगने गये, यह उनका निर्णय था, उनकी दूरदृष्टि थी। यह समाज की चेतना है कि समाज में उठने वाले प्रश्नों के समाधान कैसे खोजे जाते हैं। सही व्यक्ति पर सही दृष्टि पड़ जाए तो दुनिया कहां से कहां पहुंच जाती है। इस लिहाज से यह हमारा स्वर्णिम समय है, जिसका नेतृत्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। हम मानकर



चल रहे हैं, हम बाहर के दुश्मनों से निपटने में भी समर्थ हैं और अपनी आंतरिक समस्याओं को भी हल करने में सक्षम हैं। सरकार और समाज मिलकर समस्याओं का हल करने में जुट जाए तो समस्याएं जल्द हल हो सकती हैं। बाल अधिकार संरक्षण आयोग बच्चों को लेकर जो चिंतन-मनन करेगा, उस पर सरकार अमल करेगी। हमारी महिला बाल विकास मंत्री निर्मला भूरिया का मन भी निर्मल है, वह अपने कार्य के प्रति समर्पित भी हैं। वो इस क्षेत्र में बेहतर काम कर रही हैं। हम मिलकर बच्चों और महिलाओं के अधिकारों के प्रति चेतना जगाएं और समस्याओं को दूर करने का प्रयास करें।



भोपाल में मंत्रालय के समक्ष वंदे मातरम का गायन किया गया इस मौके पर युवा खेल कल्याण मंत्री विश्वास सारंग एवं मुख्य सचिव अनुराग जैन सहित मंत्रालय के कई अधिकारी कर्मचारी उपस्थित रहे।

सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला अब दृष्टिहीन भी बन सकते हैं जज

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए कहा कि देश में दृष्टिहीन लोग भी जज बन सकते हैं। शीर्ष अदालत ने कहा कि दृष्टिहीन लोगों को भी न्यायिक सेवाओं में नियुक्त किए जाने का अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट ने दृष्टिहीन व्यक्तियों को न्यायिक सेवाओं में नियुक्त किए जाने के अधिकार को बरकरार रखा है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश न्यायिक सेवा नियम हट कर दिया है। जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस आर महादेवन की पीठ ने यह फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश न्यायिक सेवा नियम को खारिज कर दिया। जिसके तहत दृष्टिहीन लोगों को न्यायिक सेवाओं में नियुक्ति के लिए चयन प्रक्रिया में भाग लेने से रोका दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने न्यायिक सेवाओं में दृष्टिहीन लोगों की नियुक्ति से संबंधित स्यो मोटो मामले में यह फैसला सुनाया है। इस मामले की उत्पत्ति मध्य प्रदेश में न्यायिक नियुक्तियों को नियंत्रित करने वाले नियमों में निहित है।

चीन को कंपा देगा भारत, 3500 करोड़ में भूटान के अंदर तक बनाएगा नई रेल लाइन

नई दिल्ली। अब भारतीय रेलवे असम के कोकराझर से भूटान के गेलेफू तक रेल लाइन बिछाने जा रहा है। 69.4 किलोमीटर की यह रेलवे लाइन असम के कोकराझर स्टेशन को भूटान के गेलेफू से जोड़ेगी। इसकी कुल लागत 3,500 करोड़ के आसपास होगी। यह रेलवे लाइन भारत और भूटान के बीच पर्यटन और व्यापार को बढ़ाएगी। इससे दोनों देशों के संबंध भी मजबूत होंगे। साथ ही इससे भूटान को अपना पहला रेलवे लिंक भी मिलेगा। वहीं रेलवे लिंक का निर्माण भारत सरकार की ओर से किया जाएगा। रेल लाइन बिछाने के लिए डीपीआर पूरा कर लिया गया है।



स्कूलों में स्मार्टफोन को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट ने सुनाया बड़ा फैसला

स्कूलों में बच्चों को स्मार्टफोन ले जाने से नहीं रोका जाना चाहिए

स्मार्टफोन के उपयोग की निगरानी और विनियमित किया जाना चाहिए

नई दिल्ली एजेंसी। हाईकोर्ट ने स्कूलों में स्मार्टफोन के पूर्ण प्रतिबंध के खिलाफ फैसला सुनाया है। साथ ही कोर्ट ने स्कूलों में स्मार्टफोन के इस्तेमाल के लिए कई दिशा-निर्देश भी जारी किया है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा कि स्कूलों में बच्चों को स्मार्टफोन ले जाने से नहीं रोका जाना चाहिए, लेकिन स्कूल में स्मार्टफोन के उपयोग की निगरानी और विनियमित किया जाना चाहिए। कोर्ट ने नकारात्मक परिणाम नहीं आए सामने: जस्टिस अनूप जयशम भंभाणी की पीठ ने कहा कि स्मार्टफोन को लेकर अभी तक नकारात्मक परिणाम सामने नहीं आए हैं और इसके उपयोग के कई हित हैं। स्मार्टफोन के इस्तेमाल से कक्षा में शिक्षण, अनुशासन या समग्र शैक्षिक वातावरण पर कोई नकारात्मक असर नहीं पड़ता है।



दुरुपयोग के खतरों को किया स्वीकार

कोर्ट ने अत्यधिक स्क्रीन टाइम, सोशल मीडिया एक्सपोजर और स्मार्टफोन के दुरुपयोग के खतरों को भी स्वीकार किया। साथ ही कहा कि इन पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने के बजाय, जिम्मेदाराना उपयोग पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए।

माता-पिता से जुड़े रहने में मदद करते हैं स्मार्टफोन

जस्टिस भंभाणी ने कहा कि तकनीक शिक्षा एक अनिवार्य हिस्सा बन गई है। जिससे स्मार्टफोन पर पूर्ण प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता। अदालत ने यह भी कहा कि स्मार्टफोन छात्रों को अपने माता-पिता से जुड़े रहने में मदद करते हैं, जिससे उनकी सुरक्षा और संरक्षा बढ़ती है।

स्कूलों में स्मार्टफोन के उपयोग के लिए दिशानिर्देश

1- जहां तक संभव हो स्कूल के समय छात्रों को अपने स्मार्टफोन जमा करा देना चाहिए। 2- स्कूल वाहनों और कक्षाओं में स्मार्टफोन का उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। 3- छात्रों को ऑनलाइन व्यवहार, डिजिटल शिष्टाचार और स्मार्टफोन के नैतिक उपयोग के बारे में शिक्षित करना चाहिए। 4- छात्रों को अत्यधिक स्क्रीन समय के खतरों के बारे में जागरूक किया जाना चाहिए, जिसमें चिंता, ध्यान अवधि में कमी और साइबर बدمशीरी शामिल हैं।

आवश्यकता पड़ने पर स्मार्टफोन कर सकते हैं जब्त

कोर्ट ने यह भी सुझाव दिया कि आवश्यकता पड़ने पर स्कूल अनुशासनात्मक उपाय के रूप में स्मार्टफोन जब्त कर सकते हैं। न्यायालय के आदेश की एक प्रति केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई), शिक्षा निदेशालय, दिल्ली सरकार और केंद्रीय विद्यालय संगठन को भेजी गई है।

रीजन चेयरपर्सन एमजेएफ लायन डॉ. अंशु सिंह की रीजन कॉन्फ्रेंस रिजु-तृषा का भव्य आयोजन



साँध्य प्रकाश संवाददाता ● भोपाल

लायंस इंटरनेशनल डिस्ट्रिक्ट 3233 की रीजन येलो की रीजन चेयरपर्सन एमजेएफ लायन डा अंशु सिंह की रीजन कॉन्फ्रेंस ऋजु- तृषाका भव्य आयोजन 2 मार्च को होटल आमेर ग्रीन्स में प्रतिष्ठित 2000 लायन सदस्यों और अधिकारियों की उपस्थिति में प्रातः 10.30 से 2.30 तक सम्पन्न किया गया। इस अवसर पर कार्यक्रम की मुख्य वक्ता पास्ट इंटरनेशनल डायरेक्टर और लायंस इंटरनेशनल फाउंडेशन की ट्रस्टी, लायन डॉ अरुणा अभय ओसवाल विशेष रूप

से दिल्ली से भोपाल पधारी ,और अपने ओजपूर्ण और प्रेरक वक्तव्य से उपस्थित जन समूह को सराबोर कर दिया । रीजन चेयरपर्सन डॉ अंशु सिंह द्वारा बताया कि इस कार्यक्रम में क्लब स्तर और जोन स्तर पर की गई सेवा गतिविधियों की सराहना की गई ,और सेवा मनीषियों को सेवा पुरुस्कारों से सम्मानित किया गया । इस अवसर पर समाज में अपने कार्यों आसे लोगों के आदर्श बनने वाले विशिष्ट व्यक्तित्वों को इममिनेंट पर्सनालिटी अवार्ड से सम्मानित किया गया और सीमा सक्सेना, सचिव लायन वंदना गुप्ता एवं कोषाध्यक्ष लायन



सुषमा कुलश्रेष्ठ हैं। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में पिपरिया से डिस्ट्रिक्ट गवर्नर पीएमजेएफ लायन मनीष शाह ,डिस्ट्रिक्ट कैबिनेट सेक्रेटरी लायन उर्वशी शाह, उज्जैन से विशिष्ट अतिथि एमजेएफ लायन प्रवीण वशिष्ठ, एमजेएफ लायन डॉ जेपी जौहर,एमजेएफ लायन महेश मालवीय एवं मुख्य संरक्षक डॉ आर.के. चौरसिया के अतिरिक्त लगभग 12 पास्ट डिस्ट्रिक्ट गवर्नर उपस्थित हुए । इस अवसर पर भोपाल के विभिन्न लायंस क्लब द्वारा मेडी बैंक, शिक्षा-रिक्शा,ई वेस्ट, पर्यावरण से संबंधित सेवा स्टाल

की गतिविधियां प्रदर्शित किये गये ।इस कार्यक्रम में भोपाल,उज्जैन, विदिशा ,पिपरिया,नागदा और इटारसी आदि डिस्ट्रिक्ट के लायन सदस्य उपस्थित हुए। रीजन के क्लब के अध्यक्ष , सचिव,कोषाध्यक्ष जोन चेयरपर्सन आदि पदाधिकारियों का अवार्ड देकर सम्मान किया गया। परमानेंट प्रोजेक्ट के लिए एमजेएफ लायन अनिता मिश्रा,एमजेएफ लायन सीमा सक्सेना ,लायन विजय अव्यर, लायन कुशल धर्माणी, लायन डॉ संजय जैन आदि विशेष अवार्ड द्वारा सम्मानित हुए।

बच्चों को हम जैसा बनाएंगे, जैसा सिखाएंगे, वैसे बनकर वह आगे बढ़ेंगे: राज्यमंत्री कृष्णा गौर



भोपाल। पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्रीमती कृष्णा गौर ने कहा कि बच्चे गीली मिट्टी के समान होते हैं। इनको हम जैसा बनाएंगे, जैसा सिखाएंगे वैसे बनकर वह आगे बढ़ेंगे। उन्होंने यह बात अवधपुरी में एक निजी स्कूल के शुभारंभ अवसर पर कहीं। राज्यमंत्री श्रीमती गौर ने कहा कि यह पहला ऐसा स्कूल है, जिसमें वह सारी सुविधाएँ हैं, जो सुविधाएँ छोटे बच्चों को मिलनी चाहिए। स्कूल में बहुत छोटी-छोटी चीजों का ध्यान रखा गया है जो बच्चों की सुरक्षा का, बच्चों के मनोरंजन का, बच्चों के ज्ञान का, हर दृष्टि से यहाँ आने वाला बच्चा हर तरफ से समृद्ध होकर जाए। इस दृष्टि से हमारा यह प्री स्कूल निश्चित रूप से हमारी नई पीढ़ी को संस्कारित करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाएगा। पार्षद मधु शिवनानी, जितेंद्र शुक्ला, मंडल अध्यक्ष सुरेंद्र दुबे, गणेश राम नागर, पार्षद श्री वी शक्ति राव, राजेश्वर सिंह, स्कूल की प्रिंसिपल रुचि विनोद सिंह, रामेश्वर भैया, विनोद सिंह, प्रसाद पटेल और सभी गणमान्य नागरिक बंधु मौजूद रहे।

पीथमपुर में अब तक यूनियन कार्बाइड का 6750 किलोग्राम कचरा जला

भोपाल। उच्च न्यायालय जबलपुर द्वारा रित याचिका क्रमांक 2802/2004 (आलोक प्रताप सिंह विरुद्ध यूनियन ऑफ इंडिया एवं अन्य) में विगत 18 फरवरी 2025 को पारित आदेशानुसार यूनियन कार्बाइड के अपशिष्ट का प्रथम ट्रायल रन 27 फरवरी 2025 से मेसर्स पीथमपुर इंडस्ट्रीयल वेस्ट मैनेजमेंट प्रा.लि. पीथमपुर, जिला धार द्वारा संचालित इसीनरेटर में किया जा रहा है।

संभागायुक्त श्री दीपक सिंह ने बताया कि आज 02 मार्च,2025 को शाम 05 बजे तक 6750 किलोग्राम अपशिष्ट का दहन किया जा चुका है। अपशिष्ट के साथ लगभग 6750 किलोग्राम लाईम भी मिलाकर दहन किया गया है। प्लू गैसेस की सफाई हेतु लगभग 7500 किलोग्राम लाईम, 3750 किलोग्राम एकटीवेटेड कार्बन तथा 50 किलोग्राम सल्फर का उपयोग किया गया। अपशिष्ट को जलाने हेतु लगभग 33 हजार लीटर डीजल की खपत हो चुकी है। अपशिष्ट के दहन के दौरान

चिमनी से हो रहे इमीशन की लगातार मॉनिटरिंग केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के लगभग 20 अधिकारी / कर्मचारियों द्वारा की जा रही है। साथ ही इमीशन के लगातार मॉनिटरिंग के लिये ऑनलाईन कन्टीन्युअस इमीशन मॉनिटरिंग सिस्टम भी संचालित है। चिमनी से उत्सर्जन निर्धारित मानक सीमा के भीतर पाये जा रहे हैं।

संभागायुक्त श्री सिंह ने बताया कि पार्टीक्यूलेट मेटर का उत्सर्जन 9.6 मिलीग्राम/सामान्य घनमीटर है, जिसकी निर्धारित अधिकतम मानक सीमा 50 मिलीग्राम/सामान्य घनमीटर है। इसी तरह सल्फर डाईऑक्साइड का उत्सर्जन 70 मिलीग्राम/सामान्य घनमीटर है, इसकी अधिकतम मानक सीमा 200 मिलीग्राम/सामान्य घनमीटर है। नाईट्रोजन ऑक्साईड्स का उत्सर्जन 116 मिलीग्राम/सामान्य घनमीटर है, इसकी निर्धारित अधिकतम मानक सीमा 400 मिलीग्राम/सामान्य घनमीटर है।

हिंदू महासभा के राष्ट्रीय महासचिव देवेन्द्र पांडे पहुंचे भोपाल, हुई बैठक



भोपाल। अखिल भारत हिंदू महासभा के राष्ट्रीय महासचिव देवेन्द्र पांडे के भोपाल आगमन पर प्रदेश अध्यक्ष रोहित दुबे की अध्यक्षता में अखिल भारत हिंदू महासभा के प्रदेश कार्यालय में शाम को 7 बजे बैठक संपन्न हुई और बैठक का विषय गौ माता को लेकर घोषित हो और 17 तारीख दिल्ली में बैठक रखी गई है उसको लेकर चर्चाएं की गई और बैठक में उपस्थित सभी हिंदू महासभा उपस्थित रहे गौरव शर्मा प्रदेश शासन संगठन मंत्री राकेश मिश्रा प्रदेश विधि अध्यक्ष शांतनु महोरकर कोषाध्यक्ष ओम हिंदू भोपाल संभाग गौ रक्षा अध्यक्ष बलराम प्रजापति भोपाल जिला उपाध्यक्ष रवि गुप्ता भोपाल उपाध्यक्ष एवं सभी हिंदू भाई उपस्थित रहे सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ में नेतृत्व में आज पूरे भारत में गौ माता को लेकर जो की गौ माता को राष्ट्रीय माता घोषित हो को लेकर पूरे भारत में भ्रमण कर रहे हैं जगह-जगह बैठक हो रही है भारत सरकार के नाम भोपाल कलेक्टर साहब को 8 मार्च को ज्ञापन देने जा रहे हैं ज्ञापन का विषय सिर्फ गौ माता को राष्ट्रमाता का दर्जा दिया जाए।

विक्रमादित्य महोत्सव में मिलेगी सिंधी गीत, संगीत व संस्कृति की झलक

चार दिनी समारोह को लेकर समिति की हुई बैठक, महोत्सव को लेकर बनाई गई रूपरेखा

संत हिरदाराम नगर। लुप्त होती सिंधी परम्परागत भग्त, सिंधी छेज, पल्लव एवं बहिराणों साहिब की एक बार फिर झलक इस बार भी चार दिवसीय वीर विक्रमादित्य महोत्सव में देखने को मिलेगी। किशोर तेजवानी की अध्यक्षता में रविवार 2 मार्च को हुई विक्रमादित्य महोत्सव समिति की बैठक में 7 मार्च से प्रस्तावित समारोह की तैयारियों की समीक्षा की गई। किशोर तेजवानी ने बताया कि 7 मार्च को स्व. प्रेमचंद तेजवानी, नारीमल नरियानी, रूपचंद रायचंदानी एवं नारी तनवानी की स्मृति में रात 9 बजे मोहनलाल एण्ड पार्टी उल्हासनगर की सिंधी भगत होगी, जबकि 8 मार्च को विधिवत शुभारंभ सुबह 10 बजे



बहिराणा साहिब के साथ किया जाएगा जिसमें सांसद आलोक शर्मा मुख्य अतिथि होंगे जबकि विधायक रामेश्वर शर्मा अध्यक्षता करेंगे। किशोर तेजवानी के अलावा महोत्सव समिति के संरक्षक ईश्वरदास हिमथानी, सुरेश जसवानी, लख्मीचंद नरियानी,

ऑस्ट्रेलिया-इंडिया के बीच होने वाला सेमीफाइनल ही फाइनल है



प्रलय श्रीवास्तव

आगामी 4 मार्च को दुबई में ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच होने वाला सेमीफाइनल ही चैंपियन ट्रॉफी का असली फाइनल होगा. क्योंकि यदि इंडिया टीम सेमीफाइनल में साउथ अफ्रीका से भिड़ती तो इंडिया के जीत के योग 90ल थे, लेकिन अब उसे ऑस्ट्रेलिया जैसी मजबूत टीम से सामना करना होगा। ऑस्ट्रेलिया वैसे भी पहले से एक मजबूत टीम है। ऑस्ट्रेलिया के पास अच्छे बल्लेबाज, गेंदबाज और फील्डर है। वह मैच को किसी भी रुख पर ले जा सकती है। इंडिया टीम की सफलता तभी निर्भर है जब उसके बल्लेबाज चल जाए। इसलिए इंडिया टीम को कड़ी मेहनत करना होगी। अब सवाल यह उठता है कि इंडिया की टीम इलेवन कैसी होगी ? क्या कोई इसमें चेंज होगा? क्योंकि दुबई की पिच स्पिनर को सहयोग कर रही है तो टीम इंडिया में बदलाव की संभावना कम है । चार स्पिनर रखकर मैच खेलना होगा । फास्ट बॉलर शमी और हार्दिक पांड्या पहले से मौजूद हैं। दोनों का परफॉर्मेंस भी अच्छा रहा है। बल्लेबाज अपनी जगह फिट है। ऋषभ पंत को मौका नहीं दिया जा सकता, क्योंकि केएल राहुल बढिया प्रदर्शन कर रहे हैं । उन्हें इन्टरनेशनल स्तर का अनुभव भी है। एक प्रश्न अवश्य उठता है कि क्या स्पिनर रविन्द्र जडेजा की जगह हर्षित राणा को टीम में लिया जाए ,लेकिन यह सब कुछ स्पिनर को सपोर्ट कर रही पिच के कारण संभव नजर नहीं आ रहा है। जडेजा को रखना भी मजबूरी हो गई है, क्योंकि वे विषम परिस्थिति में काम आने वाले बल्लेबाज भी हैं। जिनसे एक दो विकेट के अलावा 20 से 30 रन की उम्मीद भी की जा सकती है । बोलिंग के कारण

उनकी जगह उचित है। कुलदीप यादव और अक्षर पटेल अपनी जगह बेहतर है । वरुण चक्रवर्ती ने आज के मैच में 5 विकेट चटकाए हैं तो उन्हें रखना भी जरूरी है। आज जब मैंने इंडिया-न्यूजीलैंड का पूरा मैच देखा तो यह पाया कि दोनों टीम इस तरह खेल रही थी कि जैसे उन्हें हारना ही हो। क्योंकि न्यूजीलैंड के एक को छोड़ शेष बल्लेबाज लापरवाही से खेलते पाए गए। इसका फायदा भारतीय गेंदबाजों ने उठाया । दोनों ही चाह रहे थे कि हारकर वे सेमी फाइनल में साउथ अफ्रीका को हराकर फाइनल में पहुंच जाए। इंडिया टीम ने भी यही सोचा कि यदि वह फाइनल में भी पहुंचती है तो उसका मुकाबला वैसे भी ऑस्ट्रेलिया से होना है तो क्यों न सेमीफाइनल में ही उससे मुकाबला कर लिया जाए जो उचित भी है। अब सवाल यह उठता है कि सेमीफाइनल में भारत का प्रदर्शन कैसा होगा ?? तो मेरा मत है कि यदि भारत को पहले बल्लेबाजी मिलती है और वह 270 से अधिक रन बनाता है तो उसके जीतने के चांसेस 60ल हो जाएंगे और यदि भारतीय बल्लेबाज 200 रन के आसपास ही निपट गए तो उसकी हार निश्चित है । दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया यदि ढाई सौ के आसपास रन बनाता है तो भारत के जीतने की संभावना 60ल हो जाएंगी । अगर ऑस्ट्रेलिया 300 रन के आसपास पहुंचता है तो फिर मुकाबला कड़ा होना सुनिश्चित है ।

मिलिट्री स्टेशन के पास प्राचीन शिव मंदिर में महाआरती के साथ हुआ महाप्रसादी का वितरण



भोपाल। गौतम नगर मिलिट्री स्टेशन के समीप रविवार को महा आरती और महा प्रसादी का आयोजन का हुआ संस्था संयोजक शैलेंद्र साहू ने बताया इस अवसर पर एम आई सी सदस्य और क्षेत्रीय पार्षद मनोज राठौर,जोन अध्यक्ष और पार्षद देवेंद्र भार्गव,भगवान दास ढालिया, धीरज यादव, पवन सक्सेना, शैलेश गोस्वामी, मनोज साहू,धीरज सोनी मनोज यादव,सुरेश यादव और आसपास के क्षेत्रवासियों ने हजारों की संख्या में महा आरती में भाग लेकर भंडारा ग्रहण किया यह आयोजन दोपहर 1 बजे से रात्रि तक मंदिर के सेवा धारीयों और ब्रह्मालुओं के सहयोग से जारी रहा।

प्राकृतिक चिकित्सा का दस दिवसीय आवासीय शिविर का भव्य शुभारंभ

संत हिरदाराम नगर। आरोग्य केन्द्र द्वारा आयोजित रोग निवारण एवं प्रशिक्षण मासिक शिविर के अन्तर्गत दस दिवसीय शिविर का शुभारंभ किया गया। इस शिविर में विभिन्न स्थानों से कई साधक लाभांन्वित होने की उम्मीद से आए हैं। यहां शिविरार्थियों को प्राकृतिक उपचार, योग, उपवास एवं अपक्व आहार, रसाहार, फलाहार के माध्यम से स्वस्थ रहने की कला सिखाई जाएगी। शिविर के प्रथम दिन शिविरार्थियों के पंजीयन एवं परामर्श प्राकृतिक चिकित्सकों द्वारा किया गया एवं इसके बाद शिविर का शुभारंभ व्याख्यान मेडीकल डायरेक्टर डॉ गुलाब राय टेवानी द्वारा दिया गया।

डॉ गुलाब राय टेवानी ने शिविरार्थियों को संबोधित करते हुए बताया कि यहा आपका पंच तत्वों से उपचार किया जाएगा जैसे पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश।



स्वस्थ जीवन प्राप्त करने के लिए एक ही उपाय है, अपनी अस्वस्थ दिनचर्या में परिवर्तन कर स्वस्थ दिनचर्या को अपनाना। आप अपनी दिनचर्या में परिवर्तन करेंगे तो ही

आप स्वास्थ्य लाभ पा सकेंगे। साथ ही यह बताया गया कि अपक्व आहार लेंगे तो दवाईया भी कम होगी। अगर बीमारी से पूर्णतः निजात पाना है तो प्राकृतिक चिकित्सा को अपनाना होगा। अगर आप स्वयं को बीमार महसूस करेंगे तो बीमार रहेंगे इसलिए मन से यह सोचना है कि हम पूर्णतः स्वस्थ हो जाएंगे क्योंकि मन के हारे हार है मन के जीते जीत। इस शिविर में शरीर शुद्धिकरण के साथ-साथ चिकित्सकों का भी शुद्धिकरण होता है, हमें हमेशा सकारात्मक सोच रखनी चाहिए कि हम स्वस्थ है।

प्रदेश के 10 नगरों में नक्शा कार्यक्रम लागू, सम्पत्ति लेन-देने की प्रक्रिया बनेगी सरल

भोपाल। नगरीय विकास एवं आवास विभाग ने प्रदेश के 9 जिलों के 10 नगरों में नक्शा कार्यक्रम लागू किया है। इसे केन्द्रीय भूमि संसाधन विभाग ने डिजिटल इण्डिया लैण्ड रिकॉर्ड्स और मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम के तहत शुरू किया है। नक्शा कार्यक्रम (नेशनल जियो स्पेटियल नॉलेज बेस्ड लैण्ड सर्वे ऑफ अर्बन हेबिटेसेशन) सम्पत्ति लेन-देन और ऋा प्राप्ति को सरल बनायेगा। यह कार्यक्रम प्रापर्टी टैक्स कलेक्शन में सुधार और वित्तीय स्थिति को सुदृढ़ करेगा। प्रदेश में यह कार्यक्रम 9 जिलों के 10 नगरों में लागू किया जा रहा है। इनमें शाहगंज, छनेरा, अलीराजपुर, देपालपुर, धार कोटी, मेघनगर, माखन नगर (बाबई), विदिशा, साँची और उन्हेल शामिल हैं। नक्शा कार्यक्रम के अंतर्गत चयनित नगरों में जियो स्पेटियल मैपिंग करना और भूमि सर्वेक्षण में आधुनिक तकनीकों का प्रयोग करना शामिल है। प्रदेश में ई-नगरपालिका के माध्यम से सभी नागरिक सेवाएँ ऑनलाइन प्रदाय की जा रही हैं। योजना के दूसरे चरण में पोर्टल के अंतर्गत 16 मॉड्यूल तथा 24 नागरिक सेवाएँ शामिल की जा रही हैं। इसी के साथ इनका डाटा प्रबंधन क्लाउड सेवाओं द्वारा प्रतिस्थापित किया जा रहा है। ई-नगरपालिका 2.0 में जीआईएस एकीकरण और ऑर्टीफिशियल इंटेलीजेंस का उपयोग किया जा रहा है। कॉमन सर्विस सेंटर, एमपी ऑनलाइन कियोस्क सेंटर और भुगतान गेटवे के साथ ई-नगरपालिका 2.0 का एकीकरण किया जा रहा है। प्रदेश के नगरीय निकायों में स्व-चालित भवन योजना अनुमोदन प्रणाली (एबीपीएस 3.0) के माध्यम से पूर्व में आ रही कठिनाइयों को दूर किया जा रहा है। उन्नत परियोजना एबीपीएस 3.0 में जीआईएस टेक्नोलॉजी, ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म और कॉलोनी विकास अनुज्ञा से संबंधित समस्त प्रक्रियाओं से जुड़ी आधुनिक तकनीकों को शामिल किया गया है।

भगवान श्रीकृष्ण ने प्रकृति से प्रेम और ग्राम संस्कृति को सम्मान देने की शिक्षा दी है: मुख्यमंत्री डॉ. यादव

महिलाओं ने अपनी लेखनी से समाज को दिशा दी: मंत्री सुश्री भूरिया

प्रदेश के सबसे बड़े इस्कॉन मंदिर का किया भूमिपूजन, इस्कॉन मंदिर को कोलार रोड से जोड़ने वाले मार्ग का नाम प्रभुपाद मार्ग होगा



साँध्य प्रकाश संवाददाता ● भोपाल

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि भगवान श्रीकृष्ण ने प्रकृति से प्रेम और ग्राम संस्कृति को सम्मान देने की शिक्षा दी है। राज दरबार में सोने-चांदी और मोती माणिक्य के बीच मोर पंख को अपने शीश पर धारण कर सम्मान प्रदान करना प्रकृति से प्रेम का प्रतीक है। भगवान श्रीकृष्ण का यह भाव बताता है कि मनुष्य मात्र से प्रेम ही प्रभु प्राप्ति का सच्चा मार्ग है। भगवान श्रीकृष्ण का सुदामा को सम्मान देना, जीवन में मित्रता के महत्व और मित्र के सम्मान के लिए प्रतिबद्धता को प्रतिपादित करता है। भगवान श्रीकृष्ण के जीवन के प्रसंगों से हमें कई व्यावहारिक शिक्षाएं प्राप्त होती हैं। मुख्यमंत्री डॉ. यादव कोलार रोड क्षेत्र में मानसरोवर डेंटल कॉलेज के पास इस्कॉन द्वारा बनाए जा रहे श्री श्री राधा

गोविंद मंदिर के भूमि पूजन के बाद उपस्थित जन समुदाय को संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर विधायक श्री रामेश्वर शर्मा, इस्कॉन के मध्यप्रदेश प्रमुख गुरु प्रसाद स्वामी महाराज तथा सचिव महामन प्रभु उपस्थित थे। कार्यक्रम में बताया गया कि यह मध्यप्रदेश का सबसे बड़ा इस्कॉन मंदिर होगा। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने क्षेत्र में इस्कॉन मंदिर स्थापना की पहल की सराहना करते हुए कहा कि मंदिर निर्माण, लोगों पर सुख-आनंद, वैभव और उनके कल्याण का मार्ग प्रशस्त करता है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कोलार रोड से इस्कॉन मंदिर को जोड़ने वाले मार्ग का नाम प्रभुपाद मार्ग रखने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि भारत की सभी दिशाओं में प्रभु श्री राम और भगवान श्रीकृष्ण की उपस्थिति की सहज ही अनुभूति होती है। विश्व में भी वर्षों से भारत, भगवान श्री राम

सिनर्जी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का शुभारंभ किया



भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने साकेत नगर भोपाल में सिनर्जी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का गणेश पूजन और दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ किया। इस अवसर पर पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक कल्याण राज्यमंत्री श्रीमती कृष्णा गौर, अस्पताल के संस्थापक डॉ. निवेश सेहरा उपस्थित थे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने अस्पताल के विशेषज्ञता विभागों, उपलब्ध कराई जाने वाली सेवाओं और सुविधाओं का अवलोकन किया।

और भगवान श्री कृष्ण की धरती के रूप में जाना जाता है, मंदिर निर्माण भागवद्भाव के साकार रूप लेने का माध्यम है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा ऐसी कामना है कि भूमि-पूजन के बाद मंदिर में भगवान श्री कृष्ण के प्रकटीकरण और मंदिर के लोकार्पण का अवसर शीघ्र ही आएगा, । मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने विश्व में भारतीय सांस्कृतिक मूल्यों और सात्विक जीवन प्रणाली के प्रसार में प्रभु पाद के योगदान की सराहना की। उन्होंने कहा कि इन विचारों के अनुरूप ही राज्य सरकार,

महानिपेध की दिशा में कार्य कर रही है, इसीलिए प्रदेश के 17 स्थानों में शराबबंदी की व्यवस्था लागू की गई है। प्रदेश में नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के साथ सहयोग से दूग्ध उत्पादन 9ब से 20ब तक ले जाने की कार्य योजना का क्रियान्वयन जारी है। यह प्रयास हमारी मूल संस्कृति की ओर लौटने के लिए किया जा रहा है। इससे खेती और पशुपालन के माध्यम से किसानों की आय बढ़ाने और दूध की पौष्टिकता से लोगों का स्वास्थ्य बेहतर बनाने में सहयोग मिलेगा।

हिंदी लेखिका संघ का 30वां वार्षिक कृति पुरस्कार एवं सम्मान समारोह आयोजित

भोपाल। लेखन समाज का दर्पण होता है। जब एक लेखिका अपनी रचनाओं के माध्यम से महिलाओं की स्थिति, उनके अधिकारों, उनके संघर्षों और उनके उत्थान की बात करती है, तो वह केवल अपनी ही कहानी नहीं बयां करती, बल्कि वह उन सभी महिलाओं की बात करती है जो मौन हैं, जो संघर्ष कर रही हैं और जो बदलाव की प्रतीक्षा कर रही हैं। यह बात महिला बाल विकास मंत्री निर्मला भूरिया ने कहीं। वे हिंदी भवन के सभागार में हिंदी लेखिका संघ मध्यप्रदेश द्वारा आयोजित 30 वां वार्षिक कृति पुरस्कार एवं सम्मान समारोह 2024-25 में संबोधित कर रही थी। सुश्री भूरिया ने कहा कि लेखन समाज के हर वर्ग को संदेश देता है। महिला लेखिकाओं का योगदान अमूल्य है और हम सभी को इसे पहचानने और प्रोत्साहित करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि हिन्दी साहित्य का इतिहास समृद्ध और विविधताओं से भरा हुआ है, जिसमें नारी का योगदान एक अहम् और विशिष्ट स्थान रखता है। हमारे देश के साहित्य में अनेक महान लेखिकाओं का योगदान रहा है, जिन्होंने न केवल



समाज में विद्यमान सामाजिक कुरीतियों और भेदभाव को उजागर किया, बल्कि उन्होंने अपने लेखन के माध्यम से नारी के अधिकारों की लड़ाई भी लड़ी। यही कारण है कि हमें यह समझने की जरूरत है कि हमें यह समझने की जरूरत है कि महिला लेखिकाओं ने केवल साहित्य में ही नहीं, बल्कि समाज में भी एक नई दिशा का संचार किया है। मंत्री भूरिया ने कहा कि प्रारंभ में महिला लेखकों को पुरुष लेखकों के मुकाबले कम मान्यता मिलती थी। लेकिन समय के साथ हमारे समाज और साहित्य में बदलाव आया है। आज ऐसी अनेक महिला लेखिकाएं हैं, जिन्होंने अपने लेखन से साहित्यिक जगत को एक नया आयाम दिया है। महिला लेखिकाओं ने हर क्षेत्र में अपनी उपस्थिति दर्ज की है। चाहे वह कहानी हो, कविता हो, उपन्यास हो या निबंध हो, हर रूप में उनकी आवाज़ सुनाई दी है। महिला-बाल

विकास मंत्री सुश्री भूरिया ने कहा कि यह सम्मान समारोह नई लेखिकाओं के लिए एक प्रेरणा का स्रोत बनेगा। हमें यह समझने की जरूरत है कि साहित्य में नया दृष्टिकोण, नयी सोच और नवाचार की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। आज हम जिन लेखिकाओं को सम्मानित कर रहे हैं, उन्होंने न केवल साहित्य की दुनिया को समृद्ध किया है, बल्कि वे अपने लेखन के माध्यम से समाज के हर वर्ग, हर मुद्दे को जागरूकता और संवेदनशीलता से पेश कर रही हैं। उन्होंने कहा कि हिन्दी लेखिका संघ द्वारा आयोजित यह सम्मान समारोह सिर्फ एक कार्यक्रम नहीं, बल्कि यह महिला लेखन के प्रति हमारी न्यायसंगत समझ और समर्पण का प्रतीक है। हम सभी को मिलकर यह सुनिश्चित करना होगा कि महिलाएं अपने लेखन के माध्यम से अपनी आवाज़ उठाएं और समाज में बदलाव लाने में सक्षम हों।

दवा विक्रेता संघ ने उप मुख्यमंत्री का किया सम्मान

दवा विक्रेताओं की भी पीड़ित मानवता की सेवा में महत्वपूर्ण भूमिका है: उप मुख्यमंत्री शुक्ल



रीवा। उप मुख्यमंत्री राजेन्द्र शुक्ल ने कहा है कि पीड़ित मानवता की सेवा में दवा विक्रेताओं की भी महत्वपूर्ण भूमिका है। केन्द्र सरकार द्वारा प्रारंभ किए गए निरोगी काया अभियान में होने वाली निशुल्क जाँच कराने के लिए लोगों को जागरूक करने का कार्य दवा विक्रेता संघ करे ताकि अधिक से अधिक लोग इसका लाभ ले सकें। उप मुख्यमंत्री का रीवा जिला दवा विक्रेता संघ द्वारा सम्मान किया गया। उप मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम में टीवी रोग से पीड़ित मरीजों को पूरक आहार किट वितरित किए। सम्मान समारोह में उप मुख्यमंत्री राजेन्द्र शुक्ल ने कहा कि देश में स्वास्थ्य सुविधाओं की वृद्धि हुई है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में स्वास्थ्य के क्षेत्र में अभूतपूर्व कार्य किए जा रहे हैं। आम आदमी को स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए आयुष्मान योजना वरदान बनी है। रीवा में भी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में गंभीर रोगों का इलाज आयुष्मान कार्डधारियों को निशुल्क हो रहा है। श्री शुक्ल ने कहा कि केन्द्र सरकार द्वारा 20 फरवरी से 31 मार्च तक संचालित निरोगी काया अभियान में बीपी, शुगर एवं लीवर की निशुल्क जाँच की जा रही है। कार्यक्रम में जिला पंचायत अध्यक्ष नीता कोल, अध्यक्ष नगर निगम श्री व्यंकटेश पाण्डेय, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष माया सिंह, समाजसेवी राजेश पाण्डेय, प्रदीप गौतम सुमन, दवा विक्रेता संघ के अध्यक्ष तरुणेंद्र सिंह, विजय सिंह, सतीश मिश्रा सहित बड़ी संख्या में दवा विक्रेता संघ के पदाधिकारी व सदस्य उपस्थित रहे।

शिवमहापुराण कथा में हुए शामिल उप मुख्यमंत्री



रीवा। दुर्गाजी मंदिर परिसर, थाना के पास रामपुर बधेलान में विधायक विक्रम सिंह द्वारा कराई जा रही शिवमहापुराण कथा में हुए शामिल। उपमुख्यमंत्री श्री राजेंद्र शुक्ल ने इस अवसर पर व्यास पीठ पर विराजित राजगुरु बंदी प्रणनाचार्य जी से आशीर्वाद प्राप्त किया और शिव महापुराण की कथा का श्रवण किया। रामपुर बधेलान के विधायक श्री विक्रम सिंह और श्री मती शिवांगी सिंह द्वारा स्व हर्ष नारायण सिंह पूर्व मंत्री की पुण्य तिथि पर रामपुर बधेलान में 25 फरवरी से 5 मार्च तक शिव महापुराण कथा का आयोजन किया जा रहा है। उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने स्व हर्ष नारायण सिंह जी के छाया चित्र पर पुष्प अर्पित कर अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए।

बसामन मामा गौवंश वन्य विहार गौ सेवा का आदर्श स्थल बनेगा : उप मुख्यमंत्री शुक्ल

गोबर व गौमूत्र से बनने वाले उत्पादों का विक्रय कर गौवंश वन्य विहार को आत्मनिर्भर बनाया जाएगा

उप मुख्यमंत्री ने गौवंश वन्य विहार में प्रशासनिक भवन का किया लोकार्पण

साँध्य प्रकाश संवाददाता ● भोपाल

उप मुख्यमंत्री राजेन्द्र शुक्ल ने कहा है कि बसामन मामा गौवंश वन्य विहार गौ सेवा का आदर्श स्थल बनेगा। गौवंश वन्य विहार में अधोसंरचना व विकास के अधिकतर कार्य पूर्णता की ओर हैं। गौवंश वन्य विहार में संरक्षित गौवंश के गोबर व मूत्र से बनने वाले उत्पादों का विक्रय कर इसे पूर्णतः आत्मनिर्भर बनाया जाएगा। शुक्ल ने एक करोड़ रुपए की लागत से बनाए गए प्रशासनिक भवन गौ कार्यालय का लोकार्पण किया।

गौ कार्यालय के नवनिर्मित हाल में समीक्षा बैठक के दौरान उप मुख्यमंत्री ने गौवंश वन्य विहार में शेष कार्यों की विभागवार जानकारी प्राप्त की। उन्होंने कहा कि गौवंश वन्य विहार में जल की निर्बाध आपूर्ति होती रहे इसलिए आवश्यक है कि भूजल स्तर कम न हो। उन्होंने गौवंश वन्य विहार से लगे तालाब को नदी से भरने के निर्देश दिए। द्वितीय चरण के तहत नाला में रपटा कम स्टॉपडेम, चेकडेम तथा शेष बाउन्ड्रीवाल के निर्माण कार्य को



स्वीकृत कर कार्य प्रारंभ करने के निर्देश बैठक में दिए गए। उन्होंने कहा कि निर्बाध विद्युत आपूर्ति की व्यवस्था सुनिश्चित कराई जाए। आगामी समय में सब स्टेशन का भी निर्माण कार्य कराया जाएगा। उप मुख्यमंत्री ने बैठक में गौवंश वन्य विहार में गौ सेवा के लिए प्रोटोकाल बनाकर कार्य किए जाने की बात कही। उन्होंने कहा कि संरक्षित गौवंश का डाटा शीट में पूर्ण विवरण दर्ज किया जाए। उन्होंने कहा कि गोबर व गौमूत्र से बनने वाले उत्पादों का विक्रय कर गौवंश वन्य विहार को पूर्णतः आत्मनिर्भर बनाया जाएगा। गोबर से बनने वाली खाद का विक्रय किया जाएगा। किसानों को गोशाला से जोड़ने का कार्य प्राथमिकता से होगा ताकि वह यहाँ से जरूरत के अनुसार खाद क्रय कर सकें। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि बायोगैस प्लांट को शीघ्र प्रारंभ किया जाए तथा मृत पशुओं के

निष्पादन की यूनिट लगाने का काम शीघ्र प्रारंभ कराएँ। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि बसामन मामा गौवंश वन्य विहार का आदर्श संचालन सुनिश्चित कराते हुए गौ सेवा के साथ ही इसे पूर्णतः आत्मनिर्भर बनाया जाएगा। उप मुख्यमंत्री ने गौवंश वन्य विहार में निर्मित रेस्ट हाउस में रात्रि विश्राम किया तथा प्रातःकाल भ्रमण कर व्यवस्थाओं का अवलोकन करते हुए गौवंश के चारा एवं गुड़ खिलाया। इस दौरान अध्यक्ष जिला पंचायत श्रीमती नीता कोल, पूर्व विधायक केपी त्रिपाठी, अपर कलेक्टर श्रीमती सपना त्रिपाठी, सीसीएफ राजेश राय, एसडीएम राजेश सिन्हा, त्रिगुणीनारायण शुक्ल, अमित अभयरामदास महाराज, समाजसेवी राजेश पाण्डेय, अधीक्षण यंत्री विद्युत मण्डल बृजेश शुक्ला कार्यपालन यंत्री हाउसिंग बोर्ड अनुज प्रताप सिंह सहित अधिकारी व जनप्रतिनिधि और ग्रामीणजन उपस्थित रहे।

ईवीएम के बाद अब पेपरलेस बूथ के माध्यम से चुनाव पर विचार

लोकतंत्र की प्रयोगशाला है पंचायत एवं नगरीय निकाय निर्वाचन: राज्य निर्वाचन आयुक्त श्रीवास्तव

साँध्य प्रकाश संवाददाता ● भोपाल

पंचायत एवं नगरीय निकाय चुनाव में ईव्हीएम के बाद अब पेपरलेस बूथ की कल्पना को मूर्त दिया जा रहा है। पंचायत उप निर्वाचन में चुनाव पेपरलेस बूथ के माध्यम से सफलतापूर्वक कराये जा चुके हैं। मध्यप्रदेश के राज्य निर्वाचन आयुक्त मनोज श्रीवास्तव ने यह बात राज्य निर्वाचन आयोग की 31वाँ नेशनल कॉन्फ्रेंस में कही। कॉन्फ्रेंस पंच जिला सिवनी में आयोजित की गई है। राज्य निर्वाचन आयुक्त ने कहा कि राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा कराये जाने वाले पंचायत एवं नगरीय निकाय निर्वाचन लोकतंत्र की प्रयोगशाला और परीक्षण स्थली हैं। पूरी दुनिया के साथ भारत का यह अनुभव है कि जब भी निर्वाचन संबंधी कोई महत्वपूर्ण प्रयोग होते हैं, तो सबसे पहले स्थानीय

निर्वाचनों में होते हैं। जब महिलाओं को प्रतिनिधि संस्थाओं में आरक्षण का विचार आया, तो सबसे पहले पंचायतों और स्थानीय निकायों में इसे लागू किया गया। मध्यप्रदेश में तो निकायों में पहले 33 प्रतिशत और बाद में 50 प्रतिशत आरक्षण महिलाओं को दिया गया है। इसकी जितनी स्वीकार्यता पिछड़े कहे जाने वाले ग्रामीण क्षेत्रों में हुई, उतनी वरिष्ठ स्तरों पर अभी भी नहीं हो पाई।

राज्य निर्वाचन आयुक्त मनोज श्रीवास्तव ने कहा कि त्रिस्तरीय पंचायत एवं नगरीय निकाय निर्वाचन लोकतंत्र की नींव हैं। यह चुनाव पूरी निष्पक्षता और पारदर्शिता से कराना हम सबकी जिम्मेदारी है। इस चुनाव के माध्यम से नागरिक सीधे शासन और निर्णय लेने की प्रक्रिया में भागीदार बनते हैं। उन्होंने ऑनलाइन वोटिंग पर चर्चा करते हुए कहा कि यह प्रयोग पहली बार एस्टोनिया में किया जा चुका है। श्रीवास्तव ने कहा कि प्रौद्योगिकी में तेजी से हो रहे परिवर्तनों के मद्देनजर यह जरूरी है कि हम चुनाव प्रणाली की विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए



प्रक्रिया में बदलाव करते रहें। राज्य निर्वाचन आयुक्त श्रीवास्तव ने कहा कि चुनावी खर्च कम करने के उद्देश्य से राज्यों के बीच ईव्हीएम शेयरिंग होना चाहिए। उन्होंने कहा कि कॉन्फ्रेंस में राज्य निर्वाचन आयुक्त उनके राज्य में किए गए नवाचारों को साझा करेंगे। इससे अन्य राज्यों में भी उसे लागू किया जा सकेगा। कॉन्फ्रेंस की अध्यक्षता असम के राज्य निर्वाचन आयुक्त आलोक कुमार ने की। इस दौरान विभिन्न राज्य निर्वाचन आयोग के नवाचारों को समाहित कर लिखी गई पुस्तक एक्स-चेंज एक्स-पीरियंस

इनीशिएटिव-2025 का विमोचन किया गया। मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव अभिषेक सिंह ने स्थानीय निकायों की निर्वाचन प्रक्रिया में पेपरलेस बूथ प्रणाली तथा इंटरग्रेटेड पोलिंग बूथ मैनेजमेंट सिस्टम को अपनाने की कार्ययोजना पर प्रजेंटेशन दिया। उन्होंने बताया कि पेपरलेस बूथ प्रणाली में डिजिटल टूल्स अपनाने से स्थानीय निर्वाचन प्रक्रिया सरल होगी। सभी डॉक्यूमेंटेशन डिजिटल होंगे तथा मानवीय भूल की संभावना भी कम होगी। उन्होंने बताया कि डिजिटल टूल्स

का उपयोग होने से चुनाव में लगने वाले अमले की संख्या में कमी आएगी तथा चुनाव खर्च भी कम होंगे। आन्ध्रप्रदेश निर्वाचन आयोग की आयुक्त श्रीमती नीलम साहनी द्वारा स्वचालित लोकल बांडी इलेक्शन प्रक्रिया पर प्रेजेंटेशन दिया गया। उन्होंने इलेक्ट्रोल रोल मैनेजमेंट, पोल मैनेजमेंट के ऑटोमेशन प्रक्रिया पर प्रकाश डालते हुए अन्य आयुक्तों के साथ समस्या एवं सुधार की संभावनाओं पर चर्चा की। विभिन्न राज्य निर्वाचन आयोग के आयुक्तों ने निर्वाचन प्रक्रिया में सुधार के संबंध में महत्वपूर्ण सुझाव दिए। लखनादीन एसडीएम रवि सिहाग तथा सहायक कलेक्टर पंकज वर्मा द्वारा ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस और सुविधाजनक निर्वाचन प्रक्रिया के लिए नवीन तकनीकों को अपनाने के संबंध में प्रेजेंटेशन दिया। साथ ही राज्य निर्वाचन आयोग त्रिपुरा द्वारा राज्य में स्थानीय निर्वाचन प्रक्रिया पर आधारित फिल्म का प्रदर्शन किया गया। कलेक्टर सिवनी सुश्री संस्कृति जैन ने प्रथम सत्र के समापन पर आभार व्यक्त किया। कॉन्फ्रेंस में तीन और चार मार्च को भी विभिन्न विषयों पर विषय-विशेषज्ञ प्रेजेंटेशन देंगे।

परिवहन एक नई कहानी

हिमाचल में सड़क परिवहन के माध्यम से प्रदेश को ऊर्जा और भविष्य के रास्ते मिलते हैं। इन्हीं रास्तों पर परिवहन निगम की कवरटेड एक नए दस्तर में वादा कर रही हैं। वादा यह कि बसों की नस्ल बदलेगी और यह भी कि ग्रीन स्टेट के प्रमुख पार्टनर के रूप में एचआरटीसी अपना श्रृंगार करेगी। परिवहन निगम का निदेशक मंडल बने फैसलों की शिरकत में छह सौ करोड़ व्यय का खाका बना रही हैं। इन में इलेक्ट्रिक फाइलें महत्व्कांक्षी हैं और वक्त के चौराहों से आगे निकलने की एक कोशिश भी कर रही हैं। हिमाचल में परिवहन का ब्रांड एचआरटीसी सदा रही है, लेकिन समय के बदलते स्वरूप और जनता की अपेक्षाओं के अनुरूप कुछ फासले ऐसे बड़ गए कि सार्वजनिक क्षेत्र के इस उपक्रम को कुछ कदम रोकने पड़े। अनावश्यक रूट घटा कर तथा संचालन की उपयोगिता बढ़ा कर, एचआरटीसी के सफर की अपनी कहानी दुरुस्त करने की कोशिशें बढ़ गई हैं। यही परिणाम पिछले एक साल में 70 करोड़ की कमाई बढ़ा कर मिला है। हालांकि इस कमाई की बाहों में इलेक्ट्रिक बसों की कम खर्चीली दास्तान है या परिवहन विस्तार पर लगे अंकुश है, फिर भी यह आशाजनक संकेत है कि एक घाटे वाले सार्वजनिक उपक्रम ने कुछ हटकर करने की ठान ली है। बहरहाल परिवहन निगम अपनी कमान बढते तथा बसों की नई खेप उतारने के लिए छह सौ करोड़ का प्रावधान सरकार के बही खातों से हासिल करेगा, वरना हर डिपो की वित्तीय व्यवस्था में इतना लाभ होता कि हर साल अपनी कमाई से ऐसी उलटबिधियां भी हासिल करता। डिपो केवल बस स्टूटों की नुमाइश से एक सीमित सा प्रबंधन बने हैं, जबकि साल दर साल की वित्तीय रिपोर्ट नकारात्मक होती गई। अगर हम डिपो दर डिपो पृछें कि कितने नालायक चल रहे हैं, तो मालूम होगा कि सियासी बस रूटों पर घाटे के ही पांव चल रहे हैं। आखिर खरोद-फरोख के केंद्रीय विषय क्यों हैं।

क्यों नहीं हर बस डिपो अपनी वित्तीय, बजटीय प्लानिंग व आमदनी एवं खर्च के ब्यौरे से हर साल, प्रगति और विकास का रिपोर्ट काई बनाए। उदाहरण के लिए हर बस डिपो अपनी कमाई से अर्जित मुनाफे से कम से कम पांच नई बसों की खरीद का वार्षिक कैलेंडर क्यों न बनाए। अगर प्राइवेट वोल्वो बस आपरेटर अपने लक्ष्यों की कामयाबी में हर साल कुछ नई बसें जोड़ लेता है, तो उसकी व्यवस्था और सफलता के मायने सिद्ध होते हैं। बेशक एचआरटीसी के मायने सार्वजनिक परिवहन को इतना संतुष्ट करते हैं कि आज भी आम हिमाचली सरकारी बसों पर भरोसा करता है, लेकिन इसका आर्थिक पक्ष और वित्तीय प्रबंधन का भी साबित करना होगा। निदेशक मंडल अपने दायित्व के खाके में 2९7 इलेक्ट्रिक व 250 डीजल बसों की खरीद पुखा कर रहा है। इसके अलावा 24 सुपर डीलेसेस बसों की खरीद भी सुनिश्चित हो रही है। जाहिर है इससे मंतव्य और गंतव्य दोनों में एचआरटीसी की छवि में सुधार होगा, लेकिन निगम को अपने बिगड़े कलपुर्जों को भी तेल लगाना पड़ेगा। यानी घाटे कम करने के लिए अनावश्यक खर्चें, अनावश्यक बस रूट और भारी भरकम अफसरों की तादद से निजात चाहिए। परिवहन के दारोमदार में नवाचार, नए विकल्पों का आधार तथा आनलानइन सुविधाओं का प्रसार भी आवश्यक है। आय बढ़ाने के लिए एचआरटीसी अपनी संपत्तियों का बेहतर इस्तेमाल करते हुए प्रमुख मार्गों तथा खान-पान सुविधाओं, रिस्टॉरंट व हाई-वे पर्यटन सुविधाओं का प्रसार कर सकती है। ऐसा क्यों नहीं सोचा गया कि परिवहन निगम की कर्कशपार की दक्षता में निजी वहन भी सुविधाएं प्राप्त कर सकें। प्रदेश में माल ढुलाई की अपार संभावनाओं में एचआरटीसी की भूमिका अलग से विंग के मार्फत परागत हो सके।

क्यों नहीं परिवहन निगम मालानी, शिमला व धर्मशाला में अपने कार्यक्षेत्र के तहत इलेक्ट्रिक टैक्सियों के संचालन में प्लाई टू प्लाई सर्विस सेवा शुरू करता। पूरी पर्यटन इंडस्ट्री के बीच परिवहन निगम की प्रासंगिकता को तय करने के लिए नए दखल चाहिए। इसी तरह अगर हिमाचल के तमाम बड़े शहरों के बस स्टैंड को व्यापारिक, मनोरंजन एवं पर्यन परिसर की अधीसंरचना में समाहित किया जाए, तो हिमाचल परिवहन निगम की सफलता की संभावना बढ़ेगी। बहरहाल, हम यह उम्मीद कर रहे हैं कि छह सौ करोड़ के व्यय से कुछ तो कारवां बढेला। कुछ खटारा बसें परिदृश्य से हट जाएंगी और कुछ क्षेत्रों में इलेक्ट्रिक बसों का बेड़ा उतर जाएगा। इन सबसे और आमदनी को बढ़ाने के लिए किराया दरों में बढ़ोतरी का सुझाव भी आया है, जहां न्यूनतम किराए की सीमा में चंद सिक्के बड़ जाएंगे।

साइबर अपराधियों में भारतीय क्यों ?

यह जानकर आप परेशान हो सकते है कि म्यांमार और पूर्वी एशिया के कई देशों से जो संगठित साइबर अपराध संचालित हो रहे हैं, उनके चंगुल में बड़ी संख्या में भारतीय युवा भी हैं। हाल ही में म्यांमार के दुर्गम इलाकों में बनाये गए साइबर अपराधियों के अड्डों से सतर भारतीय युवाओं को छुड़या गया है। जिनको डरा-धमकाकर भारत में साइबर अपराधों को अंजाम देने के लिये इस्तेमाल किया जाता था।

बताया जाता है साल 2022 के बाद म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया आदि से छह सौ से अधिक भारतीयों को अपराधियों के चंगुल से बचाया जा चुका है। आशंका है कि कई हजार भारतीय युवा म्यांमार समेत विभिन्न देशों में साइबर अपराधियों के अड्डों में जबरन रोके गए हैं। दुर्भाग्यपूर्ण है कि भारतीय युवा प्रतिभाएं दलालों की साजिश से संगठित साइबर अपराध करने वाले अंतर्राष्ट्रीय अपराधियों के चंगुल में फंस जाती हैं। विडंबना ही है कि हम अपने युवाओं को न तो रोजगार दे पा रहे हैं और न ही विदेशों में अपना भविष्य सव्गारने की आकांक्षा रखने वाले युवाओं को फर्जी एजेंटों के चंगुल से बचा पा रहे हैं। अखिर हमारी एजेंसियां ऐसी धोखाधड़ी करने वाले एजेंटों पर नकेल क्यों नहीं कस पा रही हैं।

हाल के दिनों में कई ऐसे मामले प्रकाश में आए हैं कि युवा अपनी जमीन बेचकर व कर्ज उठाकर विदेश जाते हैं, लेकिन एजेंटों की धोखाधड़ी से वे साइबर अपराधियों के अड्डों में फंस जाते हैं। दरअसल, साइबर अपराधियों का मकड़जाल इतना मजबूत हो चुका है कि बिना अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के उन पर नियंत्रण कर पाना संभव न होगा। ऐसे वक्त में जब साइबर अपराधियों का नेटवर्क दुनिया की आर्थिकी को चुनौता रहा है, मिल-जुलकर इनके खिलाफ अभियान चलाना वक्त की जरूरत है। निश्चित रूप से यह विषय एक सिकट संकट है, जिसे दुनिया के देशों को गंभीरता से लेने की जरूरत है। यह जानते हुए कि साइबर अपराधियों का संगठन लगातार ताकतवर होता जा रहा है और वे समानांतर काली अर्थव्यवस्था चला रहे हैं।

दरअसल, हो यह रहा है कि देश-दुनिया में ऑनलाइन फ्रॉड लगातार बढ़ते जा रहे हैं। वे सुनहरे सपने दिखाकर बेरोजगार युवाओं को फंसाते हैं। उन्हें जाह कोई और बतायी जाती है और अंततः-साइबर अपराधियों के अड्डों पर पहुंचा दिया जाता है। युवाओं के पासपोर्ट छीन लिए जाते हैं। ये अड्डे ऐसी जगहों पर होते हैं कि उस देश की पुलिस की पकड़ में वे आसानी से नहीं आते। हाल के वर्षों में साइबर अपराधी इतने चतुर-चालाक हो गए हैं कि निगरानी करने वाली एजेंसियां की पकड़ से आसानी से बच जाते हैं। हाल ही में जिन सत्तर भारतीयों को म्यांमार में साइबर अपराधियों के चंगुल से मुक्त कराया गया, उसमें म्यांमार के सीमा सुरक्षा बल की कई भूमिका रही है। इन मुक्त कराए गए भारतीयों में पंजाब, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, यूपी व राजस्थान आदि राज्यों के लोग थे। इसी तरह हम्यांम व अन्य पूर्वी एशिया के देशों में साइबर अपराधियों के चंगुल में फंसे हुए भारतीयों को मुक्त करने के लिए इन देशों की सरकारों से सहयोग मांगा जाना चाहिए।

निश्चित तौर पर साइबर अपराधियों द्वारा संचालित अपराधों की लगातार मजबूत होती काली अर्थव्यवस्था पूर्ण दुनिया की आर्थिक व कानूनी सुरक्षा के लिये चुनौती है। इस काले धन से नशे के कारोबार, आतंकवाद और मानवीय तस्करी जैसे अपराधों को अंजाम दिया जाता है। इस संगठित आपराधिक नेटवर्क पर अविलंब अंकुश लगाने की जरूरत है। जिससे न केवल एक तरह से बंधक बनाये गए युवाओं को मुक्त कराया जा सकेगा बल्कि तेजी से बढ़ती ऑनलाइन ठगी पर अंकुश लग सकेगा। दरअसल, इन साइबर अपराधियों की ऑनलाइन धोखाधड़ी के कारण हर साल कई ट्रिलियन डॉलर का नुकसान विभिन्न देशों की सरकारों को हो रहा है। जो दुनिया की कई बड़ी अर्थव्यवस्थाओं की जीडीपी के बराबर है।

सामयिक चिंतन



विनोद नागर

देश की राजधानी दिल्ली में अभी चुनावी बुखार पूरी तरह उतरा भी न था कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन ने अपने बेतुके बयान से भाषाई राजनीति को गर्मा दिया है। इसमें उन्होंने केंद्र सरकार पर दक्षिण भारत में

हिन्दी भाषा को थोपने का आरोप लगाते हुए कहा है कि तमिलनाडु एक और भाषा युद्ध के लिये तैयार है। दक्षिण भारत में और खास तौर पर तमिलनाडु में हिन्दी का विरोध जग जाहिर है। स्वातंत्र्योत्तर काल से हीद्रविड़ संस्कृति और भाषाई प्रतिबद्धता के नाम पर विभिन्न राजनैतिक दल चुनावी रोटियाँ सेकते रहे हैं। हालाँकि कालांतर में सामाजिक स्तर पर इस भाषाई जड़ता का खामियाजा भी उन्हें उठाना पड़ा है।

ताजा भाषाई विवाद पर हिन्दी भाषी क्षेत्रों के साहित्यिक सांस्कृतिक हलकों में तीखी प्रतिक्रिया उभरकर सामने आई है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के प्रतिष्ठित साहित्यकार डॉ. देवेन्द्र दीपक ने स्टालिन के इस आरोप को नितान्त भ्रामक बताया है, जिसमें कहा गया है कि हिन्दी और संस्कृत के कारण उत्तर भारत की 25भाषाएँ नष्ट हो गयीं हैं। वे जिन्हें भाषा कह रहे हैं, वह हिन्दी की बोलियाँ हैं और अपने-अपने क्षेत्र में आसानी है। दरअसल,स्टालिन के संस्कृत और हिन्दी के विरोध के पीछे उनका सनातन द्वेष है।

स्टालिन का यह कहना भी एक सफेद झूठ हैकि हिन्दी उन पर थोपी जा रही है। नयी शिक्षा नीति, जिसमें पढ़ाई के लिये त्रिभाषा सूत्र अपनाया गया है, के सूत्रधार स्वयं तमिलभाषी है?। नई शिक्षा नीति में भाषा का पक्ष लोकतांत्रिक है। त्रिभाषा सिद्धांत में हिन्दी कहीं भी अनिवार्य नहीं है। एक मातृभाषा, दूसरी विदेशी भाषा और तीसरी कोई भी भारतीय भाषा?। तमिलनाडु के स्कूलों में बच्चे जो चाहें वह भाषा पढ़ें। अब इसमें हिन्दी को थोपने की बात कहीं से आ गई?

‘शिक्षा की नव क्रांति का शंखनाद’ पुस्तक के लेखक और पद्यश्री से सम्मानित वरिष्ठ पत्रकार आलोक मेहता ने स्टालिन के बयान को भाषा विरोधी बताते हुए कहा है कि तमिलनाडु ने तो बहुत पहले से अपने यहाँ त्रिभाषा फार्मुले के स्थान पर द्विभाषा फार्मुला लागू कर तमिल और अंग्रेजी को स्वीकारते हुए हिन्दी को सिरे से नकार दिया था। भाषाई द्वेष के चलते आप लोगों की भावनाओं को भड़काकर वोट भले ही कबाड़ सकते हो, लेकिन घृणा की राजनीति की भी आखिर कोई सीमा तो होनी चाहिये। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तो अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में तमिल संगमम आयोजित कर वहीं तमिल विद्वानों को आमंत्रित कर उनका मान-सम्मान किया था।

इस मामले में मप्र साहित्य अकादमी के निदेशक डॉ. विकास दामे की राय प्रामाणिकता और तथ्यों पर आधारित है। वे कहते हैं- हिन्दी, तमिल और संस्कृत सभी हमारी राष्ट्रीय भाषाएँ हैं। संस्कृत ने सदैव दक्षिण की भाषाओं को माँ की तरह पोषण दिया है। दक्षिण की भाषाओं में नाभि नाळ सम्बन्धमजैसे शब्दयुग्म सहज लोक प्रचलित हैं।स्टालिन के आराध्य के जन्म से सैकड़ों वर्ष पूर्व से यह नाभि नाळ संबंध बना हुआ है। ‘वाल्मिकी रामायण’ प्रथम राम कथा है। संस्कृत के बाद उसका प्रथम अनुवाद ‘कम्ब रामायण’ है,जो दक्षिण के संस्कृत से जुड़ाव का प्रतीक है। तमिलनाडु में रामायण के प्राचीनतम संदर्भ हमें संगम कालीन साहित्य में मिलते हैं।

सप्रै संग्रहालय के निदेशक और दादा माखनलाल

चतुर्वेदी की पत्रिका कर्मवीर के डिजिटल संस्करण के संपादक अरविंद श्रीधर मानते हैं कि तमिलनाडु अथवा किसी भी दक्षिणी राज्य में हिन्दी का विरोध केवल सियासत के लिए किया जाता रहा है। यह आज से नहीं सालों से हो रहा है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के हालिया बयान ने तो संस्कृत को भी इस विवाद में लपेट लिया है, जबकि आम धारणा के अनुसार दक्षिण भारतीय भाषाएँ संस्कृत के ज्यादा निकट हैं। राजनीतिज्ञ अपनी वोट बैंक की मजबूरी के चलते भाषाई सौहार्द पर बात करें या न करें, समाज के बुद्धिजीवियों को जरूर इस पर बात करनी चाहिए। भाषाई सौहार्द ही हिन्दी की स्वीकार्यता का विस्तार कर सकता है।

भाषा युद्ध की चेतावनी को लेकर अपने सामयिक आलेख में सुदि पत्रकार और राजनीतिक मामलों के टिप्पणीकारअजय बोकिल ने दो टूक लिखा है- हिन्दी को लेकर तमिलनाडु का विरोध 1937 से है। वह देश में अकेला ऐसा राज्य है, जहाँ स्कूलों में राजभाषा और अधोषित रूप से राष्ट्रभाषा का स्वरूप ले रही हिन्दी नहीं पढ़ाई जाती। इससे नुकसान उन बच्चों का होता है, जो तमिलनाडु के बाहर अन्य राज्यों में नौकरी-धंधा करना चाहते हैं। नतीजा यह है कि विद्यार्थी निजी स्तर पर हिन्दी सीख रहे हैं। दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार समिति द्वारा आयोजित हिन्दी परीक्षा में तमिल विद्यार्थियों की बढ़ती संख्या इसका प्रमाण है। निहितार्थ यही कि तमिलनाडु में हिन्दी का विरोध मुख्यतःराजनीतिक है और द्रविड़ राजनीति की प्रासंगिकता को बनाये रखने की चेष्टा भर है।

प्रकारांतर से यही बात मध्य प्रदेश लेखक संघ के अध्यक्ष श्री राजेन्द्र गड्डानी की फौरी प्रतिक्रिया में भी झलकती है- तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के बयान के मूल में क्षुद्र राजनीतिक स्वार्थ हैं। स्टालिन भले ही तमिलनाडु के मुख्यमंत्री और सत्तारूढ़ द्रमुक के शीर्ष नेता हैं, लेकिन उन्हें पता होना चाहिये कि जब दक्षिण की भाषाएँ संस्कृत से नष्ट नहीं हुईं तो उत्तर भारत की भाषाएँ कैसे नष्ट हो गईं? न तो राष्ट्रीय स्तर का है। अतः ऐसे बेतुके राजनीति से प्रेरित उनके वक्तव्य को ज्यादा गंभीरता से लेने की आवश्यकता नहीं है।

हिन्दी सेवियों की स्वेच्छिक संस्था ‘हिन्दी परिवार’ के संस्थापक अध्यक्ष हरeram वाजपेयी के तेवर तो और भी गरम हैं- तमिलनाडु के मुख्यमंत्री को भाषा और संस्कृति का इतिहास मालूम नहीं है। संस्कृत तो सभी भाषाओं की जननी है। लेकिन उन अपनी माँ को माँ नहीं कह सकता वह दूसरे की माँ को क्या सम्मान देगा स्टालिन चुनावी हथकंडा अपनाकरराजनीतिक मंसूबा पूरा करने के लिए अनर्गल प्रलाप कर रहे हैं।पूरे देश को उनके इस दुर्भाग्यपूर्ण वक्तव्य का विरोध करना चाहिए। ‘हिन्दी परिवार’ इन्दौर के महाश्वसित स्तोष मोहंती भी इस विवाद को पूरी तरह राजनीतिक मानते हुए कहते हैं कि वोट बैंक को पुछा करने के लिए ही यह भाषाई मुद्दा उठाया गया है।

आकाशवाणी के पूर्व समाचार वाचक, कवि, लेखक एवं स्तंभकार सदीप श्रोत्रिय भाषा की गरिमा को रेखांकित करते हुए कहते हैं- कोई भी भाषा किसी दूसरी भाषा को नष्ट नहीं करती, बल्कि वे साथ-साथ चलते हुए एक दूसरे को समृद्ध ही करती हैं। लेकिन जब राजनीति सतह पर आती है तो राजनेता एक दूसरे को शत्रु की तरह दिखाते और भाषा का इस्तेमाल हथियार की तरह करने से भी नहीं चूकते। मैंने नई दिल्ली के भारतीय जन संचार संस्थान में संस्कृत के समाचार वाचक बलदेवदा आनंद सागर से तमिलनाडु में त्रिची से आये संवाददाता को इस मुद्दे पर कई दिनों तक लड़ने की हद तक बहस करते देखा है कि द्रविड़ संस्कृत से ज्यादा पुरानी भाषा है।

वरिष्ठ साहित्यकार और गीतकार डॉ. रामवल्लभ आचार्य हिन्दी भाषा के महात्म्य को लेकर पूर्णतः आश्चस्त हैं। उनका कहना है- स्टालिन महाशय के राजनीति प्रेरित बयान से विचलित होने की जरूरत नहीं है। क्षेत्रीय पार्टियों का अस्तित्व क्षेत्रवाद की राजनीति पर ही टिका है। यदि दक्षिण भारत के लोग आज के आधुनिक युग में हिन्दी का विरोध करने के बजाय उसे संपर्क भाषा के रूप में अपनाते हैं तो इससे उनका ही भला होगा। धार्मिक पर्यटन बढ़ने से उनकी अर्थव्यवस्था और सुदृढ़ होगी। त्रिभाषा फार्मुला किसी पर हिन्दी थोपने की वकालत नहीं करता, इसलिए सारी आशंकाएँ निमूल हैं।

लघु कथा शोध केंद्र के सचिव घनश्याम मैथिल ‘अमृत’ के अनुसार तमिलनाडु सहित दक्षिण भारत के अधिकांश राज्य वर्षों से हिन्दी के विरोध की ओछी राजनीति कर स्वयं अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं। मुख्यमंत्री स्टालिन का बयान पूर्णतः राजनीति से प्रेरित और दुर्भाग्यपूर्ण है।संस्कृत तो भारत वर्ष की भाषा ही नहीं हमारी सांस्कृतिक विरासत और सभी प्रांतीय भाषाओं की जननी है।कोई माँ भला अपनी संतानों का अहित कर उन्हें नष्ट कैसे कर सकती है जब सभी भारतीय भाषाएँ और बोलियाँ समृद्ध होंगी तभी तो हिन्दी समृद्ध होगी।हमारी भाषाओं और बोलियों का असल नुकसान तो अंग्रेजी ने किया है, जोहिन्दी की जगह देश की संपर्क भाषा बन बैठी है।

वरिष्ठ साहित्यकार प्रभु दयाल मिश्र भी ताजा भाषाई विवाद से व्यथित हैं- स्टालिन की उत्तर भारतीयों में फूट डालने की कुटिल चाल सभी भारतीय अच्छी तरह से समझते हैं। तमिल भाषा और संस्कृति का कोई विरोध उत्तर भारत में नहीं है। यह भेद बुद्धि हेय और अपराध भाव जनित ही है।जैसे समस्त सभ्यताएं भारतीय बखूबी समझते हैं।

आकाशवाणी के समाचार संपादक संजीव शर्मा भाषा को कल-कल बहती नदी की तरह मानते हैं जो अपने प्रवाह क्षेत्र में जीवनदायिनी होती है लेकिन आगे बढ़ते हुए किसी और बड़ी नदी के सहारे या स्वयं समुद्र में मिल जाती है। कुछ यही हाल आंचलिक भाषाओं का है। वे अपने क्षेत्र में लम्ब्य प्रतिष्ठित हैं और विकास एवं विस्तार के क्रम में हिन्दी में व्यापक रूप से घुल मिल गई हैं। भाषा कोई जमींदार या क्रूर शासक नहीं है जो कमजोर को दबाने का प्रयास करे। बल्कि हिन्दी तो माँ के आंचल सी है ममतामयी, सभी को समाहित और सम्मान करने वाली। यदि कोई क्षेत्रीय भाषा विकास की इस दौड़ में पीछे रह गई है तो उसका ठीकरा हिन्दी पर नहीं फोड़ा जा सकता।

कवि, कथाकार, व्यंग्यकार गोकुल सोनी अपने अनुभव साझा करते हुए बताते हैं कि तमिलनाडु में हिन्दी भाषियों के प्रति जितना द्वेष का भाव अशिक्षित और कम पढ़े लिखे लोगों में है, उतना वहीं के शिक्षित लोगों में नहीं है। वे टूटी फूटी अंग्रेजी गर्व से बोल सकते हैं पर हिन्दी से उनको बैर है। 1९9९ में मैं सर्वजना सम्मेलन में भाग लेने बंगलौर गया था। वहाँ देश के हर राज्य से 15-20 साहित्यकार आये थे। मध्यप्रदेश में भी हमएक दर्जनसाहित्यकार थे।आयोजन स्थल पर हमें यह देखकर घोर निराशा हुई कि लंबे चौड़े बैनर पर करीब 15 भाषाओं में ‘सर्व भाषा सम्मेलन’ लिखा था, पर उसमें हिन्दीगायब थी।

हिन्दी की उपेक्षा से हमेंइतनी पीड़ा हुई कि हमने एक साथ खड़े होकर विरोध करने तथा सम्मेलन का बायकाट करने का निर्णय किया।तब वहाँ मौजूद मुख्यमंत्री को स्वयं मज्जी मांगनी पड़ी। उन्होंने वायदा किया कि मध्यांतर के बाद आपको बैनर पर हिन्दी में नाम लिखा मिलेगा।लेकिन मध्यांतर के बाद हमें हिन्दी में नाम लिखा हुआ तो मिला परंतु सबसे नीचे और छोटे अक्षरों में। कहने का अर्थ यही कि

राजनेताओं ने हिन्दी के प्रति घृणा के बीज वहीं के प्रत्येक व्यक्ति के मन में बो दिये हैं।

व्यंग्यकार डॉ. हरिशकुमार सिंह का मानना है कि स्टालिन ने हिन्दी द्वारा संस्कृत सहित 25 भारतीय भाषाओं को निगलने की बात राजनीतिक पैतरे के रूप में कही है।हिन्दी को थोपने का आरोप तब सही माना जाता जब नई शिक्षा नीति में हिन्दी सीखना अनिवार्य किया जाता।एक अन्य व्यंग्यकार प्रेमचंदद्वितीय के अनुसार तमिलनाडुकेसीएमका बड़बोला बयानदशकोंसेहाशिये पर पड़े भाषाईविवाद को हवा देने वाला है। देश के 53 करोड़ से अधिक लोगों कीमातृ भाषा हिन्दीहै, वहीं विश्व में 64 करोड़ सेअधिकलोगहिन्दीबोलतेहैं।अबतोवक्तहिन्दीकेविरोधका नहीं,वरनआर्थिकारिकभाषाकादार्जादिलानेकेलिएवैश्विक समर्थनजुटाने काहै।

शाशवत सृजन के संपादक और साहित्यकार सदीप सृजन कहते हैं कि दक्षिण भारत में हिन्दी विरोधी आंदोलन केवल राजनीति तुष्टिकरण का खेल है। हिन्दी की मंशा कभी अन्य भाषाओं को खत्म करने की नहीं रही है।रही बात संस्कृती की तो उसका व्याकरण संसार के श्रेष्ठतम व्याकरण में आता है, जो हर भाषा को पुष्ट कर सकता है। उज्जैन के लेखक एवं स्तंभकार सुभाष चंद्र जोशी भी इस बात से सहमत हैं कि तमिलनाडु में भाजपा के बढ़ते प्रभाव से भयभीत स्टालिन का वक्तव्य अपनी राजनीतिक जमीन बचाने का प्रयास मात्र है।

दुर्घत स्मारक पांडुलिपि संग्रहालय के संयुक्त सचिव और अध्येता सुरेश पटवा को लगता है कि यह शुद्ध राजनीति है। उत्तर दक्षिण विभाजन बहुत पुराना है। इसमें आर्य परिवार और द्रविड़ परिवार सहित भाषा विवाद पुराने जमाने से जुड़ा है।पचास से अधिक पुस्तकों का हिन्दी में अनुवाद कर चुके दिनेश मालवीय ‘अश्क’ इसे केवल एक तुच्छ राजनीतिक चाल मानते हैं। वरिष्ठ साहित्यकार एवं दोहाकार प्रभु त्रिवेदी का अभिमत है कि हिन्दी के प्रति राष्ट्रीय अनुराग और उसके बढ़ते हुए वैश्विक प्रभुत्व को देखकर स्टालिन जैसे क्षेत्रीय राजनेता को क्षुद्र राजनैतिक बयानों से परहेज करना चाहिए। अन्यथा वह समय दूर नहीं, जब सनातन के साथ संस्कृत और हिन्दी दोनों काअधिकार क्षेत्र बड़ जाएगा।

इसके विपरीत अखिल हिन्दी साहित्य सभा, अमरावती की संस्थापक अध्यक्ष शीला डोंगरे तमिलनाडु केहिन्दी विरोध को जायज ठहराती हैं, क्योंकि यह राज्य की भाषाई पहचान, सांस्कृतिक अधिकारों और सविधान द्वारा प्रदान किए गए संधीय ढांचे से जुड़ा मसला है। उसने लिए यह विरोध अपनी भाषा और संस्कृति को संरक्षितकरने की कोशिश है। हालाँकि वे यह भी कहती हैं किराष्ट्रीय एकता और संवाद के दृष्टिकोण से हिन्दी को एक साझा भाषा के रूप में बढ़ावा देना समझदारी हो सकती है। इसलिए, इस विरोध को जायज या नाजायज कहने से पहले, यह महत्वपूर्ण है कि हम राज्य की भाषा और संस्कृति की सुरक्षा, राष्ट्रीय एकता, और संवाद के माध्यमों के बीच संतुलन बनाए रखें। दोनों पक्षों के तर्कों में कुछवैधता हैऔर समाधान किसी सामंजस्यपूर्ण समझौते पर आधारित होना चाहिए।

बहरहाल,कुल मिलाकर विडम्बना यही कि आजादी के 78 साल बाद भी हिन्दी को राष्ट्र भाषा का दर्जा दिलाता तो दूर,भारत में ही निमेषवार पदों पर बैठे कुछ लोग उस पर अन्य भाषाओं को नष्ट करने के बरगलाने वाले आरोप लगाने से बाज नहीं आ रहे..। यह कड़वा यथार्थ आँखें खोलने वाला भी है और आक्रोशित करने वाला भी..!!

लोकोतंत्र की सुगंध के लिए जरूरी है, अपराधियों पर प्रतिबंध

संसदीय प्रणाली दलीय आधार पर काम करती है। यह भी आश्चर्यजनक है, कि विभिन्न राजनीतिक दल अपराधिक आरोपों वाले उम्मीदवार ही चुनाव मैदान में उतारते हैं। यह शायद इसीलिए किया जाता है, क्योंकि ऐसे उम्मीदवारों के धन बल, बाहुबल और अपराधिक छवि चुनाव जीतने में मददगार होती है। राजनीतिक दलों का पहला उद्देश्य चुनाव जीत कर सत्ता हासिल करना होता है, इसलिए जिताऊ उम्मीदवार उतारते समय अपराधिक आरोपों को दरकिनार कर दिया जाता है। लोकतंत्र और राजनेताओं के प्रति बढ़ता अविश्वास भी शायद इसीलिए है, क्योंकि चुनाव के समय तो मतदाता पूर्वाग्रह में अपना मत दे देते हैं, लेकिन बाद में पांच साल अपने कर्मों की सजा भुगतते हैं। मुफ्तखोरी की योजनाओं से मतदाताओं को प्रलोभन देने की जो नई शैली राजनीति में प्रारंभ हुई है, वह भी राजनीति में अपराधीकरण को ही प्रोत्साहित कर रही है।

नैतिकता लोकतंत्र की आत्मा होती है। अब तो सत्ता लोकतंत्र की आत्मा बन गई है। नैतिकता का तो कहीं पता नहीं है। राजनीति में नैतिकता तो जैसे परित्यक्ता हो गई है। यह जानते हुए भी, कि सारी सत्ता, सारे पद, सारे प्रतीक, सारा धन-वैभव मृत्यु छीन लेती है। केवल व्यक्ति की नैतिकता है, जो इसके बाद भी समाज का मार्गदर्शन करती है। अपराधीकरण दूसरों को नहीं स्वयं को नष्ट करता है।

राजनीति के अपराधीकरण को लोकतंत्र की मजबूरी नहीं बनाया जाए, व्यवस्थाओं के संकेत सू्रमा बनने वाले सांसों पर संकट के समय सच का सामना करते हैं.

रक्तदान शिविर में 100 यूनिट हुआ रक्तदान



औबेदुल्लागंज (संबाददाता) । भोजपुर रक्तदान कल्याण संघ द्वारा आयोजित शिविर शासकीय हॉस्पिटल में लगाया गया जिसमें अति उत्साह से नगर के युवाओं, महिलाओं,व्यापारियों और अन्य नागरिकों ने 100 यूनिट रक्तदान किया । संस्थापक तूफान सिंह राजपूत,हरपाल सिंह राजपूत एवं प्रीतम राजपूत ने बताया कि लगातार 10वीं बार शिविर का आयोजन किया गया जिसमें नगर के कई युवाओं ने पहली बार रक्तदान किया,वहीं कई रक्तदाताओं ने लगातार आठवीं बार शिविर में रक्तदान किया । रक्तदान शिविर सुबह 1० बजे से प्रारंभ हुआ जिसका शाम 5 बजे समापन हुआ ।

उक्त आयोजन में सल्येंद्र पांडे, पामेश यादव, जितेंद्र सक्सेना, सर्वेश मित्तल, डा महेंद्र सिंह धाकड़, महेश सोधिया, संदीप जयसवाल, भूपेंद्र राजपूत, लाखन सिंह, कपिल यादव, रमेश बासवानी, मनोहर नागर, चुनन्हे मियां, कमलेश लोधी, नानकराम यादव, मोहन योगी, सचिन श्रीवास्तव, बिजी लावनीया, सुरेश केवट का विशेष सहयोग रहा ।

संगम सेवालय द्वारा दीन दयाल रसोई के सामने श्री आर पार्क का निर्माण



छतरपुर। संगम सेवालय द्वारा पर्यावरण संरक्षण एवं स्वच्छता को ध्यान में रखते हुए दीन दयाल रसोई के सामने 3 पार्क का निर्माण किया गया है। इस पार्क का मुख्य उद्देश्य सिंगल यूज प्लास्टिक, पुराने कपड़े एवं टायरों का पुनः उपयोग कर उनका रचनात्मक तरीके से दोबारा इस्तेमाल करना है, ताकि लोगों को कचरा प्रबंधन व पर्यावरण बचाने का संदेश दिया जा सके।

इस पार्क में पुराने टायरों को आकर्षक ढंग से सजाकर उनमें पौधारोपण किया गया है, जिससे न केवल हरियाली बढ़ेगी बल्कि टायरों का सही उपयोग भी सुनिश्चित हुआ है। साथ ही, इको ब्रिक्स (प्लास्टिक बोतलों में भरी गई रद्दी प्लास्टिक) से सुंदर गमले तैयार किए गए हैं, जिनमें विभिन्न प्रकार के पौधे लगाए गए हैं। इसके अतिरिक्त, प्लास्टिक की पुरानी बोतलों को काटकर उनमें भी पौधे लगाए गए हैं, जो पार्क की सुंदरता को बढ़ाते हुए पर्यावरण संरक्षण का संदेश दे रहे हैं। संगम सेवालय का यह प्रयास न केवल कचरे के पुनःचक्रण (रिसाइक्लिंग) का बेहतरीन उदाहरण है, बल्कि लोगों को कचरे को रचनात्मक उपयोग में लाकर पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक करने का कार्य भी कर रहा है।

पहला रोजा रखकर, मुस्लिम समाज ने मालिक की इबादत की



सिरोंज। रविवार से रमजान का पवित्र महीना मुस्लिम समुदाय का प्रारंभ हो गया है। पहला रोजा रखकर मालिक की इबादत की दौरा भी प्रारंभ हो गया है पांच वक्त की नमाज अदा करने के बाद गोला चलने के बाद रोजा खोलने काम किया गया एक महीने तक इबादत का दौर चलेगा। वहीं मस्जिदों में भी रोजेदारों पहुंच कर नमाज पढ़ी वहीं घरों पर भी इबादत की जा रही है। रमजान में रोज रखना बहुत अच्छा बताया इसके चलते बुजुर्गों से लेकर बच्चे युवा और महिलाएं भी रोजा रखकर पूरी शिद्दत से खुद की इबादत करती हैं। दूसरी ओर बजरिया में शाम के रोजा इस्त्तार की सामग्री लेने के लिए रोज रखने वालों और उनके सपरिजन की भीड़ लगी हुई थी जगह कम होने के कारण यहां पर जाम भी लग रहा था। रमजान के पवित्र महीने प्रतिदिन रोजा रखकर इबादत का दौरा चलेगा जिसको लेकर मुस्लिम समाज जनों कई दिनों से इंजार् इस महीने का करते कर रहे थे। पहला रोजा मैं ज्यादा दिक्कत नहीं हुई अभी गर्मी ज्यादा नहीं है।अने वाले दोनों में तापमान में वृद्धि होगी तो थोड़ी बहुत दिक्कत हो सकती है पर खुद की रहमत से कोई परेशानी नहीं होती है। वहीं 6 बजाने के बाद मुस्लिम समाज की दुकानों पर ताले लग गए थे।

यातायात पुलिस ने की वाहनों की चेकिंग बनाए चालान

सिरोंज। यातायात पुलिस के द्वारा वाहन चेकिंग प्रारंभ की तो वाहन चालकों में हड़कंध मच गया पुलिस की कार्रवाई से बचने के लिए कई बाहन चालक तो दूर से ही अपने वाहनों को वापस लेकर जाते हुए नजर आए वहीं लटेरी नाकें साहित शहर में यातायात सुबेधर रितेश वाघेला की मौजूदगी में पुलिस कर्मियों ने वाहनों की जांच की जिसमें रजिस्ट्रेशन, ड्राइविंग लाइसेंस , बीमा हेलमेट, तीन सवारी और यातायात विभाग के नियमों का पालन नहीं करने पर एक दर्जन के करीब वाहनों पर चलनी कार्रवाई भी की गई कई वाहन चालक पुलिस की चालानी करवाई से बचने के लिए बहाने बनाते हुए नजर आए पर पुलिसकर्मियों ने किसी की बात पर ध्यान नहीं दिया। शहर में निरंतर ब चेकिंग होने से वाहन चालकों को चालानी कार्रवाई का सामना करना पड़ता है।

पेंशनरों की मौजूदगी में हुई विद्युत हित रक्षक संघ की बैठक

सांध्य प्रकाश बैतूल। विद्युत हित रक्षक संघ,जिला शाखा बैतूल की मासिक बैठक संघ के अध्यक्ष केआर घोड़की के मार्गदर्शन में मध्य प्रदेश विद्युत मंडल लिंक रोड टिकारी के परिसर में संपन्न हुई। बैठक में प्रांतीय प्रतिनिधि एके गुप्ता, अविनाश वर्मा, विश्वनाथ देशमुख और श्री लाडले की विशेष उपस्थिति रही। बैठक में संपन्न द्वारा सेवा निवृत्त हुए पेंशनरों का सम्मान किया गया। और सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया गया कि प्रत्येक माह सेवा निवृत्त होने वाले और उसी माह जन्मदिन मनाने वाले पेंशनरों का भी इसी प्रकार सम्मान किया जाएगा। बैठक में 178 पेंशनरों ने उपस्थिति दर्ज कराई। उनकी समस्याओं को पंजीकृत किया। संगठन के अध्यक्ष आरआर वराडे ने आवश्कत किया कि पेंशनरों के हित से जुड़े मामलों को प्रांतीय विद्युत पेंशनर हित रक्षक संघ भोपाल के मार्गदर्शन में पूरा किया जाएगा।



मुझे चार्ज लिए 04 महीने हुए हैं मैं कुछ नहीं कर सकती: तलवड़े

दवा विक्रेता तथा औषधि निरीक्षक लोगों की जान से कर रहे खिलवाड़

मंडला/अजीत पटेल -मण्डला जिला एक आदिवासी बहुल जिला है जो नर्मदा के तट पर बसा हुआ बहुत ही शांत एवं आदिवासी रीति-रिवाज की बहुल्यता में लिस है। मंडला जिले पर स्वास्थ्य व्यवस्था के पिछड़ेपन की हकीकत किसी से छुपी नहीं है। आज स्वास्थ्य विभाग में भ्रष्टाचार के साथ उदासीनता और बढ़ती लापरवाही के चलते जिले मे लोगों के स्वास्थ्य और जिंदगी से खुल्लम-खुल्ला सौदेबाजी हो रही है। वहीं जिम्मेदारों तथा आला-अधिकारी अपनी हिस्सेदारी एवं कमीशनवादी में व्यस्त हैं नतीजा जगह-जगह बगैर फार्मासिस्ट के दवाई दुकान चलाये जा रहे हैं। उक्त मामले पर औषधि निरीक्षक वैजवी तलवड़े से बात की गई तो उन्होंने यह जवाब देकर कि मुझे चार्ज लिए 4 महीने हुए हैं इसलिए मैं कुछ नहीं कर सकती साथ ही साथ एक प्रशासनिक जिम्मेदारी होने के बावजूद वैजवी तलवड़े द्वारा कि पूरे जिले भर का जिम्मा उनको सौंप दिया गया है और वो अकेले पूरे जिले में कैसे निगरानी रख सकती हैं, एक जिम्मेदार अधिकारी द्वारा दिया गया यह जवाब बहुत ही विचारणीय हो गई है।

गैर पंजीकृत दवा दुकानों द्वारा किया जा रहा लोगों की जिंदगी से खिलवाड़

मण्डला जिले में स्वास्थ्य व्यवस्था एवं उनके अमला द्वारा लोगों की जिंदगी से खुलेआम जुआं खेला जा रहा है।वहीं दूसरी ओर अपनी तिजोरी भरने की चाह में चिकित्सकों द्वारा मरीजो को दवाई किसी ब्रांडेड नाम से दवाई लिखने की होड़ मची हुई है जनरिक नाम से (साल्ट नेम) नहीं लिखी जा रही है,पहले तो यह सिर्फ बड़े-बड़े जिलो या तहसील स्तर तक ही सीमित था,परन्तु अब यह स्थिति ग्रामीण अंचलों के छोटे-छोटे गांवों तक की हो गई है।आयुष चिकित्सक और झोलाछाप डॉक्टरों जो एमबीबीएस डिग्री के बगैर खुलेआम गंभीर बिमारियों का इलाज कर रहे हैं और ऐलोपैथी दवा लिख रहे हैं,इंजेक्शन-



बॉटल लगा रहे हैं। जिले अपनी मासिक चढ़ोतरा मिलने की चाह में सीएमएचओ एवं बीएमओ द्वारा झोलाछाप डॉक्टरों को खुलेआम लोगों की जिंदगी से खेलने की आजादी दी गई है।जिले में दवा विक्रेताओं द्वारा नकली एवं जेनरिक दवाइयां लाकर प्रिंट दाम के बावजूद कम दाम में बेंचकर लाखों के मुनाफे पर इन कॉपीराइट फार्मूले तथा जेनरिक एवं नकली दवा बेंचकर लोगों की जिंदगीओं को दवा विक्रेताओं ने अपनी कमाई का जरिया बना लिया है। जिसमें अपनी हिस्सेदारी और कमीशन बटोर कर बराबर का साथ दे रहे हैं औषधि निरीक्षक विभाग तथा स्वास्थ्य विभाग के जिम्मेदार अधिकारी जिन्होंने अपनी ज्वाइनिंग का समय एवं जिले में किए जाने वाले निरीक्षण को स्वयं के द्वारा किए जा रहे भ्रष्टाचार छुपाने का जरिया बना लिया है। जिसके लापरवाही के चलते बिना किसी मान्यता-डिग्री एवं अनुभव तथा चिकित्सक के पर्वी के खुलेआम ऐलोपैथीक दवाइयां बेचकर लोगों के स्वास्थ्य एवं जिन्दगी के साथ खिलवाड

शहर के प्रमुख चौराहों और मार्गों पर नगर पालिका ने बनवाई आकर्षक वॉल पेंटिंग दे रही स्वच्छता का संदेश



सफाई कर्मी नियमित वाडों में सफाई करते हैं साथ ही कचरा कचरा वाहन में ही डालें। दुकानों के सामने डस्टबिन अवश्य रखें इधर-उधर कचरा ना फेंके कचरा डस्टबिन में ही डालें।

सफाई कर्मी नियमित वाडों में सफाई करते हैं साथ ही कचरा कचरा वाहन में ही डालें। दुकानों के सामने डस्टबिन अवश्य रखें इधर-उधर कचरा ना फेंके कचरा डस्टबिन में ही डालें।

ईवीएम के बाद अब पेपर लेस बूथ के माध्यम से चुनाव पर विचार लोकतंत्र की प्रयोगशाला हैं पंचायत एवं नगरीय निकाय निर्वाचन: राज्य निर्वाचन आयुक्त

सिवनी। पंचायत एवं नगरीय निकाय चुनाव में ईवीएम के बाद अब पेपरलेस बूथ की कल्पना को मूर्त दिया जा रहा है। पंचायत उप निर्वाचन में चुनाव पेपर लेस बूथ के माध्यम से सफलतापूर्वक करायें जा चुके हैं। मध्य प्रदेश के राज्य निर्वाचन आयुक्त मनोज श्रीवास्तव ने यह बात राज निर्वाचन आयोग की 31 वीं नेशनल कॉन्फ्रेंस में कही। कॉन्फ्रेंस पेंच जिला सिवनी में आयोजित की गई है।

श्रीवास्तव ने कहा कि राज्य निर्वाचन आयोगो द्वारा करायें जाने वाले पंचायत एवं नगरीय निकाय निर्वाचन लोकतंत्र की प्रयोगशाला और परिक्षण स्थली हैं। पूरी दुनिया और साथ ही भारत का यह अनुभव है कि जब भी निर्वाचन संवंधी कोई महत्वपूर्ण प्रयोग होते हैं तो सबसे पहले स्थानीय निर्वाचनों में होते हैं। जब महिलाओं को प्रतिनिधि संस्थाओं में आरक्षण का विचार आया तो सबसे पहले पंचायतों और स्थानीय निकायों में इसे लागू किया गया । मध्यप्रदेश में तो निकायों में पहले 33 प्रतिशत और बाद में 5० प्रतिशत आरक्षण महिलाओं को दिया गया है। इसकी जितनी स्वीकार्यता पिछड़े कहे जाने वाले ग्रामीण क्षेत्रों में हुई उतनी वरिष्ठ स्तरों पर अभी भी नहीं हो पाई। राज्य



निर्वाचन आयुक्त श्री श्रीवास्तव ने कहा कि त्रिस्तरीय पंचायत एवं नगरीय निकाय निर्वाचन लोकतंत्र की नींव है। यह चुनाव पूरी निष्पक्षता और पारदर्शिता से कराना हम सबकी जिम्मेदारी है। इस चुनाव के माध्यम से नागरिक सीधे शासन और निर्णय लेने की प्रक्रिया में भागीदार बनते हैं। उन्होंने ऑनलाइन वोटिंग पर चर्चा करते हुए कहा कि यह प्रयोग पहली बार एस्टोनिया में किया जा चुका है। श्री श्रीवास्तव ने कहा कि प्रायोगिकी में तेजी से हो रहे परिवर्तनों के मद्देनजर यह जरूरी है कि हम चुनाव प्रणाली की विश्वसनियता बनाए रखने के लिए प्रक्रिया में बदलाव करते रहें।

ईवीएम श्रेयरिंग- श्री श्रीवास्तव ने कहा कि चुनावी खर्च कम करने के उद्देश्य से राज्यों के बीच ईवीएम श्रेयरिंग होना चाहिए। उन्होंने कहा कि कॉर्ग्रेस में राज्य निर्वाचन आयुक्त उनके राज्य में किए गए नवाचारों को साझा करेंगे। इससे अन्य राज्यों में भी उसे लागू किया जा सकेगा।

जिला भाजपा कार्यालय में संगठन संबधी महत्वपूर्ण बैठक संपन्न

दमोह । भारतीय जनता पार्टी जिला कार्यालय में अति महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया गया जिसमें मुख्य अतिथि मध्यप्रदेश भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा, बैठक की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष श्याम शिवहरे, जिला प्रभारी सतानंद गौतम, संस्कृति, पर्यटन, धार्मिक न्यास एवं धर्मव्य राज्यमंत्री स्वतंत्र प्रभार धर्मेन्द्र सिंह लोधी, दमोह सांसद राहुल सिंह लोधी, हटा विधायक श्रीमती उमा देवी खटीक, पूर्व जिलाध्यक्ष प्रीतम सिंह मंचासीरों रहें।

बैठक को संबोधित करते हुए प्रदेश संगठन मंत्री हितानंद शर्मा ने नव निर्वाचित मंडल अध्यक्षों को उनके कर्तव्य, दायित्वों और आगामी भविष्य में संगठन द्वारा निर्धारित कार्यक्रमों, गतिविधियों के संबंध में विस्तार से चर्चा की । उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ता ही सर्वोपरि होता है। पद और दायित्व संगठन की दृष्टिसे आवश्यक है परंतु कार्यकर्ता और पदाधिकारी एक दूसरे के पूरक है।

इसलिए हम सभी को एक दूसरे के साथ कदम से कदम मिलाकर संगठन के कार्यक्रम करना है और संगठन को मजबूत रखना है।

जिला अध्यक्ष श्याम शिवहरे ने स्वागत भाषण देते हुए कहा कि आपके मार्गदर्शन में संगठन के कार्यक्रमों की गतिविधियों का सफल संचालन हो रहा है। आप सभी का मार्गदर्शन हम सभी को अपार ऊर्जा और उत्साह के साथ कार्य करने की प्रेरणा देता है। मैं नेतृत्व को आश्चस्त करता हूँ कि जिले का प्रत्येक कार्यकर्ता संगठन और सरकार के प्रत्येक कार्यक्रमों

सांध्य प्रकाश बैतूल ।

और शास्त्री वार्ड में दूषित पानी से लोगों को उल्टी दस्त होने की घटना सामने आने पर कलेक्टर नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी ने रविवार को मुलताई पहुंचकर प्रभावित वार्डों का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान कलेक्टर सूर्यवंशी ने घर-घर जाकर प्रभावित रहवासियों से चर्चा की और उनका हाल-चाल जाना। साथ ही गंभीर मरीजों को तत्काल अस्पताल में भर्ती कराए जाने के निर्देश स्वास्थ्य विभाग के अमले को दिए। निरीक्षण के दौरान उन्होंने वार्ड में स्थित नालियों और वॉल चैंबरों, पानी की टंकी को भी देखा। वॉल चैंबरों के आस-पास गंदा पानी डालने वालों के विरुद्ध कार्रवाई किए जाने के निर्देश आपस पालिका के अधिकारियों को दिये। इसके अलावा पानी की टंकी की सफाई करने, प्रभावित वार्डों की पुरानी पाइपलाइन बदलने के भी निर्देश नगर पालिका को दिए गए। इस दौरान लापरवाही पाए जाने पर कलेक्टर ने नगरपालिका के आरआई को तत्काल निर्लाबित किए जाने के निर्देश दिए।

बेहतर इलाज का झांसा देकर प्रशिक्षु चिकित्सकों को बुलाया जाता है

जिले में जहां दवा विक्रेताओं की कमीशन नाम चढ़ोतरी चढ़ाकर जिम्मेदारों के साथ मिलकर नकली एवं जेनरिक दवाओं से लाखों मुनाफा की कमाई चल रही है वहीं इन मेडिकल स्टोरों के संचालकों ने आमजनता को गुमराह कर बड़े-बड़े शहरों से प्रशिक्षु चिकित्सकों को बुलाकर अनुभवी चिकित्सकों की तरह बगैर किसी पंजीयन के फर्जी पर्वी में दवा लिखकर लोगों को बेहतर इलाज का झांसा दिया जाता है जिसमें स्वास्थ्य विभाग के जिम्मेदार एवं औषधि विभाग का अमला भी बराबर के जिम्मेदार है।जो यह सब जानते हुए अपनी भ्रष्टाचारी और लापरवाहियों के कारण मामले को नजरअंज कर रहे हैं।

जहां स्वयं औषधि निरीक्षक का कहना है कि उनके अकेले के द्वारा पूरे जिले में निगरानी नहीं रखी जा सकती वहीं समझ नहीं आता इन सब के झांसे के बीच मरिजो को स्ट्राइड हाई डोज इंजेक्शन लगाने और हायर एंटीबायोटिक दवाओं इंजेक्शन लगाकर आमजनता के जिन्दगी से खिलवाड़ कर शारीरिक रूप से किडनी-लीवर,दिल की गंभीर बिमारी जैसी बिमारियों का शिकार कैसे बना रहे है। स्वास्थ्य व्यवस्था तथा औषधि विभाग की इसी लापरवाही का कारण है कि मासूम बच्चों और गर्भवती महिलाओं की दवाइयां भी बगैर किसी चिकित्सक के पर्ची के दवा दुकानों में खुलेआम बेची जा रही है वहीं जिम्मेदारों द्वारा मौन होकर तमाशा देखा जा रहा है।

दूषित पानी की समस्या को लेकर मुलताई पहुंचे कलेक्टर सूर्यवंशी

आरआई को तत्काल निर्लाबित दिए जाने के दिए निर्देश

सांध्य प्रकाश बैतूल । मुलताई के तिलक और शास्त्री वार्ड में दूषित पानी से लोगों को उल्टी दस्त होने की घटना सामने आने पर कलेक्टर नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी ने रविवार को मुलताई पहुंचकर प्रभावित वार्डों का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान कलेक्टर सूर्यवंशी ने घर-घर जाकर प्रभावित रहवासियों से चर्चा की और उनका हाल-चाल जाना। साथ ही गंभीर मरीजों को तत्काल अस्पताल में भर्ती कराए जाने के निर्देश स्वास्थ्य विभाग के अमले को दिए। निरीक्षण के दौरान उन्होंने वार्ड में स्थित नालियों और वॉल चैंबरों, पानी की टंकी को भी देखा। वॉल चैंबरों के आस-पास गंदा पानी डालने वालों के विरुद्ध कार्रवाई किए जाने के निर्देश आपस पालिका के अधिकारियों को दिये। इसके अलावा पानी की टंकी की सफाई करने, प्रभावित वार्डों की पुरानी पाइपलाइन बदलने के भी निर्देश नगर पालिका को दिए गए। इस दौरान लापरवाही पाए जाने पर कलेक्टर ने नगरपालिका के आरआई को तत्काल निर्लाबित किए जाने के निर्देश दिए।

निरीक्षण के दौरान एसडीएम अनीता पटेल, पीएचई, जल संसाधन विभाग, नगर पालिका सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे।

शास्त्री और तिलक वार्ड में निरीक्षण के दौरान कलेक्टर सूर्यवंशी ने सीएमएचओ डॉ. रविकांत उईके को प्रभावित वार्डों में 24 घंटे पैरामेडिकल स्टाफ मौजूद रहने, इन वार्डों का सतत मॉनिटरिंग करने और मरीज को दवाई उपलब्ध कराए जाने के निर्देश दिए। अलावा पीएचई विभाग के अधिकारियों को दवाइयों में अलग-अलग जगह से पानी के सैंपल लेने तथा वार्ड में दवाई वितरित करने के निर्देश दिये। निरीक्षण के पूर्व कलेक्टर श्री सूर्यवंशी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचे। जहां उन्होंने सामान्य डॉक्टर और आईसीयू श्रह चिकित्सा इकाई में भर्ती उल्टी-दस्त के पीड़ित मरीजों से चर्चा की। इस दौरान उन्होंने कहा कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती मरीजों को उपचार में किसी भी प्रकार की कमी न हो। गंभीर मरीजों को जिला अस्पताल रेफर किया।

मृतक देशमुख और कुंबी समाज की प्रतिष्ठा को धूमिल करने का नारायण पर आरोप

मृतक की पत्नी ने सारनी थाने ने कार्यवाही को लेकर की लिखित शिकायत



अगर है। तो वे थाने में पेश करें। सिर्फ झूठे बयान बाजी करके मेरे मृतक पति रविन्द्र की समाज मे प्रतिष्ठा भंग की है। बल्कि कुंबी समाज को अपमानित भी किया है।

जिससे लोग भ्रमित हो रहे है। उन्होंने बताया कि वो दूसरे समाचार पत्रों की खबरों से मानसिक रूप से ग्रसित है। थाना प्रभारी ने अभी मेरे बयान नहीं लिए है। वो फिन्तहाल उनके परीक्षा देने के लिए भोपाल हैं। वापस आकर अपने समाज के अनुभवी लोगों के साथ बैतुल एस पी निश्चल झारिया से मिलेगी। श्रीमती देशमुख ने शिकायत पत्र के आधार पर उचित जांच कर कार्यवाही किये जाने की थाना प्रभारी सारनी से मांग की है।

इनका कहना है

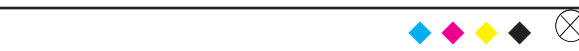
श्रीमती देशमुख ने थाने में आवेदन किया है। कल मीटिंग में था देख लेता हूँ बयान लेकर जांच की जाएगी। सही पायी जाने पर कार्यवाही भी की जा सकती है।

जयपाल इवनी साहब थाना प्रभारी सारनी

इंजी. कमलेश तेकाम बने गौडवाना गणतंत्र पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष

मण्डला/अजीत पटेल। गौडवाना गणतंत्र पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पद में इंजी. कमलेश तेकाम की नियुक्ति की गई है।यह नियुक्ति गौडवाना गणतंत्र पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व विधायक तुलेश्वर सिंह मरकाम ने की है। बता दें कि तेकाम वर्तमान में गौडवाना गणतंत्र पार्टी मंडला के जिला अध्यक्ष के पद में पदस्थ हैं।इसी के साथ वे जिला पंचायत मंडला में उपाध्यक्ष के पद में भी कार्यरत हैं। इनकी नियुक्ति पर कार्यकर्ताओं ने हर्ष व्यक्त किया है। कार्यकर्ताओं

ने कहा कि नेतृत्व क्षमता और समर्पण से पार्टी को नई ऊंचाइयां मिलेगी।।आपके नेतृत्व में पार्टी के कार्यकर्ताओं को नई ऊर्जा और उत्साह मिलेगा।गोंगपा ने मध्यप्रदेश में संगठन को मजबूत बनाने के लिये युवा नेतृत्व के हथों में कमान सौंपी है।गोंगपा से तेकाम बिछिया विधानसभा से दो बार विधानसभा का चुनावी लड़ चुके हैं। गोंगपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष तुलेश्वर सिंह मरकाम ने मध्यप्रदेश गोंगपा की जवाबदारी युवा नेतृत्व कमलेश तेकाम को सौंपकर आगामी विधानसभा चुनाव में मजबूती के साथ मध्यप्रदेश में गोंगपा के पक्ष में करने के उद्देश्य से कहा है। अध्यक्ष नियुक्त होने पर समस्त गोंगपा के कार्यकर्ताओं ने बधाई व शुभकामनायें प्रेषित की है। नियुक्ति संबंधी सवाल के जबाब में श्री तेकाम ने कहा कि पार्टी ने उन पर विश्वास जताया है और वे इस विश्वास को कायम रखेंगे।उन्होंने कहा कि कार्यकर्ताओं की छोटी मोटी समस्याओं को भी अब पूरी ताकत के साथ हल किया जाएगा।



एडलवाइज़ लाइफ़ की स्टडी से पता चलता है कि भारत में सैंडविच जेनरेशन के 60 प्रतिशत लोगों को भविष्य की फ़ाइनेंशियल सिक्वोरिटी की चिंता है

मुंबई, एजेंसी। भारत में सैंडविच जेनरेशन के लोग अपने माता-पिता और बच्चों की ज़िंदगी को हर संभव तरीके से सबसे बेहतर बनाने पर ध्यान देते हैं, फिर भी उन्हें ऐसा लगता है कि वे अपने भविष्य के लिए पूरी तरह से तैयार नहीं हैं। एडलवाइज़ लाइफ़ इंश्योरेंस की एक स्टडी के अनुसार, 60 प्रतिशत उत्तरदाता इस बात से सहमत हैं कि, चाहे मैं कितनी भी सेविंग या इन्वेस्ट कर लूँ, पर ऐसा लगता है कि ये भविष्य के लिए काफी नहीं है। सामान्य तौर पर 35 से 54 साल की उम्र के लोगों को सैंडविच जेनरेशन कहा जाता है, जिनके कंधों पर दो पीढ़ियों – यानी अपने बुजुर्ग माता-पिता और बढ़ते बच्चों की आर्थिक ज़रूरतों को पूरा करने की जिम्मेदारी होती है। जीवन बीमा कंपनी ने यूगो के साथ मिलकर देश के 12 शहरों में इस जेनरेशन के 4,005 लोगों का एक सर्वे किया, ताकि उनके नज़रिये, उनकी धारणा और वित्तीय तैयारी के स्तर को समझा जा सके। इस मौके पर एडलवाइज़ लाइफ़ इंश्योरेंस के एमडी एवं सीईओ, सुमित राय ने कहा, पिछले कुछ सालों में अपने ग्राहकों के साथ बातचीत के आधार पर हमने इस बात को करीब से जाना है कि, सैंडविच जेनरेशन के लोग किस तरह अपने माँ-बाप और बच्चों की देखभाल के बीच फंसे हुए हैं। सुमित राय ने आगे कहा, इस जनरेशन के लोग अपनी खूबाहिशों के बारे में जानते हैं और मानते हैं कि, अपनी पसंद की प्रोडक्ट कैटिगरी में निवेश करके भविष्य की अच्छी तरह से योजना बनाना बेहद जरूरी है। लेकिन हमारी इस स्टडी से कुछ दिलचस्प बातें भी सामने आई हैं। उनमें इस तरह के एक्टिव इन्वेस्टमेंट को आगे 1-2 सालों तक बरकरार रखने में काफी कम रुचि दिखाई देती है। इसके अलावा, उन्हें पहले से तय किए गए लक्ष्यों के लिए इन्वेस्टमेंट का भी समय से पहले उपयोग करना पड़ा है। उन्हें लगता है कि वे कमजोर जमीन पर खड़े हैं, जिसमें कोई हैज़ारी की बात नहीं है।

बैंक ऑफ़ बड़ौदा ने की प्रोग्रामेबल सीबीडीसी के माध्यम से बैंकिंग जगत के पहले मर्चेंट लॉयल्टी/कैशबैक प्रोग्राम की शुरुआत

मुंबई, एजेंसी। देश में सार्वजनिक क्षेत्र के अग्रणी बैंकों में से एक, बैंक ऑफ़ बड़ौदा ने भारतीय रिजर्व बैंक के मार्गदर्शन में आज व्यापारियों के लिए सेंट्रल बैंक डिजिटल करंसी की प्रोग्रामेबिलिटी प्रणाली पर आधारित मर्चेंट लॉयल्टी/कैशबैक प्रोग्राम की पायलट आधार पर शुरुआत किए जाने की घोषणा की। बैंकिंग उद्योग में यह पहली ऐसी महत्वपूर्ण पहल है, जो छोटे और मझौले व्यापारियों को एक फिन्टेक कंपनी के सहयोग से स्वतंत्र रूप से अपने ग्राहकों के लिए लॉयल्टी/कैशबैक प्रोग्राम तैयार और आरंभ करने की सुविधा प्रदान करता है। आमतौर पर इस तरह के प्रोग्राम बड़े ब्रांड्स द्वारा पुर किए जाते हैं, लेकिन अब बैंक ऑफ़ बड़ौदा के बॉब मर्चेंट ऐप के उपयोग के माध्यम से व्यापारी इसे स्वयं संचालित कर सकते हैं।

अब स्थानीय किराना दुकानें, मेडिकल स्टोर्स, रिटेल शॉप्स आदि जिनका खाता बैंक ऑफ़ बड़ौदा में है और जो बॉब मर्चेंट ऐप पर पंजीकृत हैं, वे बिना किसी अतिरिक्त निवेश के खुद का कैशबैक/लॉयल्टी प्रोग्राम डिजाइन और संचालित कर सकते हैं। उन्हें इसके लिए कोई अतिरिक्त इंफ़्रास्ट्रक्चर या सॉफ़्टवेयर खरीदने की ज़रूरत नहीं होगी। इस बारे में विस्तृत जानकारी देते हुए बैंक ऑफ़ बड़ौदा के कार्यपालक निदेशक, श्री संजय विनायक मुदालियर ने कहा, बैंक ऑफ़ बड़ौदा बैंकिंग क्षेत्र में नवोन्मेषिता को आगे बढ़ाने में अग्रणी रहा है। प्रोग्रामेबल सीबीडीसी के माध्यम से पहली बार प्रस्तुत हमारा मर्चेंट लॉयल्टी/कैशबैक प्रोग्राम भारतीय बैंकिंग जगत में नवोन्मेषी पहल है जो छोटे और मझौले व्यापारियों को अपनी आवश्यकताओं के अनुसार कैशबैक ऑफ़र डिजाइन करने की सुविधा प्रदान करती है जिससे व्यापारियों को ग्राहकों को आकर्षित करने और उन्हें जोड़े रखने में मदद मिलेगी। इस पहल से व्यापारियों और ग्राहकों दोनों को लाभ मिलेगा।

भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का भारतीय कॉर्पोरेट्स से अग्रह

मुंबई, एजेंसी। शिक्षा के क्षेत्र में 75 वर्ष पूरे करने के अवसर पर, हिंदुजा समूह ने अपने प्रमुख संस्थान, हिंदुजा कॉलेज ऑफ़ कॉमर्स के जमीए भारत के भविष्य को आकार देने की अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की। हिंदुजा कॉलेज ऑफ़ कॉमर्स की शुरुआत शरणाथियों के बच्चों के लिए बनाए गए एक साधारण प्राथमिक विद्यालय के रूप में हुई थी। आज 6000 से अधिक छात्र यहां पढ़ते हैं और हिंदुजा कॉलेज ऑफ़ कॉमर्स अब एक डीम्ड विश्वविद्यालय बनने की ओर अग्रसर है। आज यह समूह हिंदुजा फाउंडेशन के माध्यम से भारत भर में रोड टू स्कूल और रोड टू लाइवलीहुड जैसी पहलों के माध्यम से 7,00,000 से अधिक छात्रों की शिक्षा प्रदान करता है। 2030 तक 1 मिलियन छात्रों को सशक्त बनाने की महत्वाकांक्षी योजनाओं के साथ, हिंदुजा फाउंडेशन शिक्षा को बदलाव के मुख्य स्त्रोत के रूप में बढ़ावा देना जारी रखता है और 2047 तक भारत के विकसित भारत के दृष्टिकोण में प्रमुख योगदान देता है। इस समारोह के मुख्य अतिथि के रूप में भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और उनके साथ कई प्रतिष्ठित गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। महाराष्ट्र के राज्यपाल श्री सी. पी. राधाकृष्णन भी विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित थे। मानीयी उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने छात्रों को उनकी उत्कृष्ट शैक्षणिक और पाठ्येतर उपलब्धियों के लिए सम्मानित किया। हिंदुजा कॉलेज के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित एक समारोह में छात्रों और गणमान्य व्यक्तियों को संबोधित करते हुए, भारत के मानीयी उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ ने कहा, सनातन को देश की संस्कृति और शिक्षा का हिस्सा होना चाहिए क्योंकि यह समावेशिता का प्रतीक है और इसमें अच्छी तरह से निहित रहने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने कॉर्पोरेट इंडिया से विशेष संस्थान बनाने के लिए शिक्षा में निवेश करने का भी आग्रह किया।

88,000 के पार जा सकता है सोना

मुंबई। इस साल की शुरुआत से अब तक सोने की कीमतों में 8,310 यानी 10.5 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है। 1 जनवरी को सोना 79,390 प्रति 10 ग्राम के स्तर पर था, जो अब बढ़कर 87,700 प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया है। चांदी की कीमतों में लगातार तीसरे दिन गिरावट देखी गई, जो 2,100 गिरकर दो हफ्ते के निचले स्तर 96,400 प्रति किलो पर पहुंच गई। पिछले सेशन में चांदी 98,500 प्रति किलो पर बंद हुई थी। ऐसे में सवाल यह उठता है कि क्या सोने-चांदी में खरीदारी करे या नहीं एक्सपर्ट्स की मानें तो सोने की कीमतों में गिरावट की उम्मीदें धूमिल होती नजर आ रही हैं। बता दें सोने की कीमतों में शुक्रवार, 28 फरवरी को गिरावट देखी गई, जो नवंबर के बाद से सबसे बड़ी साप्ताहिक गिरावट है। अमेरिकी डॉलर के मजबूत होने के कारण सोने पर दबाव बना, क्योंकि निवेशक फेडरल रिजर्व की मॉड्रिक नीति के संकेतों के लिए अमेरिकी मुद्रास्फीति डेटा का इंतजार कर रहे थे। बता दें सोने के भाव सोमवार को अमेरिकी डॉलर की कमजोरी और ग्लोबल ट्रेड बाधा का आशंकाओं के बीच बढ़ोतरी के साथ कारोबार कर रही हैं। स्पाट गोल्ड 0.3 प्रतिशत बढ़कर 2,868.29 डॉलर प्रति औंस पर पहुंच गया, जबकि अमेरिकी गोल्ड फ्यूचर्स 1.1 प्रतिशत बढ़कर 2,880.70 डॉलर प्रति औंस पर पहुंच गया। मेहता इक्विटी लिमिटेड के वीपी मोहोडिंजी राहुल कलंतरी ने लाइव मिनट से कहा, सोने और चांदी की कीमतों में एक बार फिर गिरावट देखी गई, क्योंकि डॉलर इंडेक्स में मजबूती आई है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने मैक्सिको और कनाडा पर नए टैरिफ लगाने की घोषणा की है।

पूर्व SEBI प्रमुख माधवी पुरी बुच पर FIR दर्ज करने का आदेश, शेयर बाजार में धोखाधड़ी का आरोप

मुंबई, एजेंसी। मुंबई की एसीबी अदालत ने पूर्व सेबी प्रमुख माधवी पुरी बुच और 5 अन्य के खिलाफ कथित शेयर बाजार धोखाधड़ी और नियामक उल्लंघनों के आरोप में एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया। अदालत ने भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरी (एसीबी) वर्ली को आदेश दिया कि वह माधवी पुरी बुच, ऑल टाइम मेम्बर अश्विनी भाटिया, अनंत नारायण, कमलेश चंद्र वर्शनेय, ऋश्म के श्रृधर सुंदरमन राममूर्ति और पूर्व चेयरमैन प्रमोद अग्रवाल के खिलाफ स्रद्धा दर्ज करें। विशेष एसीबी अदालत के न्यायाधीश, शशिकांत एकनाथराव बागड़ ने पारित आदेश में कहा इन व्यक्तियों के खिलाफ नियमों में चूक और मिलीभगत के प्रथम दृष्टया सबूत मिले हैं, इसलिए इसमें एक निष्पक्ष जांच की आवश्यकता है। अदालत ने कहा कि वह जांच की गिराणी करेगी, और 30 दिनों के भीतर मामले की स्थिति रिपोर्ट मांगी।

अदालत के आदेश में यह भी जिक्र किया गया कि पांचों आरोपियों के खिलाफ जो आरोप लगे हैं वह सज़ानीय अपराध की प्रकृति के हैं, जिसके लिए जांच की दरकार

शेयर गिरा, घाटा बढ़ा, ओला इलेक्ट्रिक के हजार कर्मचारियों की छुट्टी

मुबई। भारत की प्रमुख इलेक्ट्रिक स्कूटर निर्माता कंपनी ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी लिमिटेड ने अपने खर्चों को नियंत्रित करने और बढ़ते घाटे को कम करने के लिए 1,000 से अधिक कर्मचारियों और कॉन्ट्रैक्ट पर काम कर वर्कर्स को नौकरी से निकालने का फैसला किया है। सूत्रों के अनुसार, यह छंटनी कई विभागों में की गई है, जिनमें खरीद, सप्लाई, कस्टूमर रिलेशन और चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर शामिल हैं। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं। यह पिछले 5 महीनों में दूसरी बार है, जब ओला इलेक्ट्रिक ओला इलेक्ट्रिक ने छंटनी की है। बता दें कि कंपनी को सॉफ्टबैंक ग्रुप कॉर्प का सपोर्ट है, इसके बावजूद भी पिछले कुछ महीनों से कंपनी संकट का सामना कर रही है। हाल ही में



है। कोर्ट ने कहा कानून प्रवर्तन (एजेंसियों) और भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सेबी) की निष्क्रियता के कारण दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) के प्रावधानों के तहत न्यायिक हस्तक्षेप की आवश्यकता है। इस केस के शिकायतकर्ता ने आरोपियों के खिलाफ कथित जांच की मांग की थी। शिकायतकर्ता एक मीडिया रिपोर्टर हैं और उन्होंने कहा है कि इस मामले में बड़े पैमाने पर वित्तीय धोखाधड़ी, नियामक उल्लंघन और भ्रष्टाचार शामिल हैं। आरोप में कहा गया है कि एक कंपनी को 1992 के सेबी अधिनियम और उसके तहत नियमों और विनियमों के अनुपालन के बिना स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टिंग की गई थी। आरोप में कहा गया है कि इस लिस्टिंग में नियामक एजेंसियां, खास

कंपनी के दिसंबर तिमाही के घाटे में 50ब की वृद्धि देखी गई, जिससे बाजार नियामकों और उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरणों ने भी उस पर नजर रखनी शुरू कर दी। नवंबर 2023 में ओला इलेक्ट्रिक ने लगभग 500 कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया था। मार्च 2024 के अंत तक कंपनी में लगभग 4000 कर्मचारी कार्यरत थे, जिनमें से इस बार 25ब से अधिक ऑपरेशन को ऑटोमेशन करने पर जोर दे रही है, जिससे कंपनी के खर्चों में कमी लाई जा सके। ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट के मुताबिक कंपनी ने अपने फ्रंट-एंड ऑपरेशन को रिकॉनाइज्ड एंड ऑटोमैटिक किया है, जिससे मुनाफे में सुधार, लागत में कटौती और

तौर से सेबी की सक्रिय मिलीभगत रही है। शिकायतकर्ता ने दावा किया कि सेबी के अधिकारियों अपनी वैधानिक जिम्मेदारी निभाने में नाकामयाब रहे हैं। आरोप लगाया गया कि सेबी ने बाजार में हेरफेर को शह दिया और एक ऐसे कंपनी को लिस्टिंग की इजाजत दिया जो तय मानदंडों को पूरा नहीं करती थी। शिकायतकर्ता ने कहा कि पुलिस स्टेशन और संबंधित नियामक निकायों से कई बार संपर्क करने के बावजूद, उनके द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई।

हिंडनबर्ग ने बुच पर लगाए थे आरोप भारत की पहली महिला सेबी प्रमुख बुच पर अमेरिका स्थित शॉर्ट-सेलर हिंडनबर्ग की ओर से हितों के टकराव के आरोप लगाए गए थे और इसके बाद राजनीतिक दबाव का सामना करना पड़ा था। पूर्व सेबी प्रमुख ने शुक्रवार को अपनी तीन साल की अर्वांध पुरी को थी और रिटायर हो गई। पिछले अगस्त में, बुच पर इस्तीफा देने का दबाव डाला गया जब हिंडनबर्ग रिसर्च ने उन पर हितों के टकराव का आरोप लगाया। हिंडनबर्ग ने आरोप लगाया था कि अदाणी समूह में हेरफेर और धोखाधड़ी के दावों की जांच को रोक दिया। हिंडनबर्ग ने माधवी बुच और उनके पति धवल बुच पर आरोप लगाया था।

कस्टूमर एक्सपीरियंस को बेहतर बनाने में मदद मिली है। साथ ही अनावश्यक पदों को हटाकर उत्पादकता बढ़ाई गई है।इसके अलावा कंपनी अपने शोरूम और सर्विस सेंटरों में काम कर रहे सेल्स, सर्विस और वेयरहाउस स्टाफ को छंटनी भी कर रही है। इस छंटनी का मुख्य उद्देश्य लॉजिस्टिक्स और डिलीवरी रणनीति को पुनः व्यवस्थित करना है, जिससे ऑपरेटिंग कॉस्ट को कम किया जा सके। ओला इलेक्ट्रिक के शेयरों में अगस्त 2023 में आईपीओ की जबरदस्त शुरुआत के बाद से 60ब तक की गिरावट आई है। कंपनी को पिछले कुछ सालों में कस्टूमर शिकायतों, सोशल मीडिया पर आलोचनाओं और बाजार हिस्सेदारी में गिरावट का सामना करना पड़ा है।

कस्टूमर एक्सपीरियंस को बेहतर बनाने में मदद मिली है। साथ ही अनावश्यक पदों को हटाकर उत्पादकता बढ़ाई गई है।इसके अलावा कंपनी अपने शोरूम और सर्विस सेंटरों में काम कर रहे सेल्स, सर्विस और वेयरहाउस स्टाफ को छंटनी भी कर रही है। इस छंटनी का मुख्य उद्देश्य लॉजिस्टिक्स और डिलीवरी रणनीति को पुनः व्यवस्थित करना है, जिससे ऑपरेटिंग कॉस्ट को कम किया जा सके। ओला इलेक्ट्रिक के शेयरों में अगस्त 2023 में आईपीओ की जबरदस्त शुरुआत के बाद से 60ब तक की गिरावट आई है। कंपनी को पिछले कुछ सालों में कस्टूमर शिकायतों, सोशल मीडिया पर आलोचनाओं और बाजार हिस्सेदारी में गिरावट का सामना करना पड़ा है।

शराब प्रेमियों के लिए राहत भरी खबर, छत्तीसगढ़ में अंग्रेजी शराब 10 प्रतिशत तक होगी सस्ती

रायपुर, एजेंसी। छत्तीसगढ़ में शराब प्रेमियों के लिए अच्छी खबर है। वित्तीय वर्ष 2025-26 की आबकारी नीति को साय कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है, जिसमें अंग्रेजी शराब की कीमतों में 10 प्रतिशत तक की कटौती का फैसला लिया गया है। गोवा से लेकर ब्लू लेबल जैसी प्रीमियम शराब अब सस्ती होगी, क्योंकि सरकार ने इन पर लगने वाला आबकारी शुल्क हटा दिया है। यह निर्णय बजट से ठीक एक दिन पहले लिया गया। छत्तीसगढ़ देश में शराब खपत के मामले में पांचवें स्थान पर है। राज्य की करीब 40ब आबाजी शराब का सेवन करती है। पिछले वित्तीय वर्ष में सरकार ने 11 हजार करोड़ रुपये के राजस्व का लक्ष्य रखा था, खासकर चुनावी साल को देखते हुए, जब शराब की बिक्री बढ़ने की उम्मीद थी।

मुकेश अंबानी की कंपनी पर लगाई गई 125 करोड़ रुपए की पेनाल्टी

मुंबई। मुकेश अंबानी की अगुवाई वाली कंपनी रिलायंस न्यू एनर्जी लिमिटेड पर पेनाल्टी लगाई गई है। मामले की जानकारी रखने वाले लोगों के अनुसार कंपनी पर यह पेनाल्टी बैटरी प्लांट लगाने में असफल रहने पर लगाई है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कोशिश है कि विदेशी ईंपोर्ट्स में कटौती की जाए। बता दें, रिलायंस न्यूज एनर्जी लिमिटेड उन कुछ कंपनियों में से एक थी। जिन्होंने बैटरी सेल मैनुफैक्चरिंग के लिए सफल बोली लगाई थी। पीएम मोदी की अगुवाई वाली सरकार की कोशिश है कि बैटरी सेल के मोचें पर लोकर प्रोडक्शन को बढ़ाया जाए। जिसके विदेशों पर निर्भरता कम हो। इसी को देखते हुए 2022 में सरकार ने बोलियां आमंत्रित की थी। जिसमें रिलायंस न्यू एनर्जी लिमिटेड ने सफल बोली लगाई थी। बिजनेस स्टैंडर्ड की रिपोर्ट के अनुसार लेकिन अब डेडलाइन मिस होने की वजह से 125 करोड़ रुपये की पेनाल्टी लगाई गई है। रिपोर्ट के अनुसार रिलायंस न्यू एनर्जी लिमिटेड अलावा राजेश एक्सपोर्ट्स लिमिटेड पर भी इतनी ही पेनाल्टी लगाई गई है। कंपनी को एंडर्वांस केमेस्ट्री सेल प्रोग्राम के लिए पेनाल्टी लगाई है। बता दें, इन कंपनियों की तरफ से अभी तक कोई भी आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है।

सीनियर आईएएस मोहम्मद सुलेमान का वीआरएस मंजूर अब करेंगे ये काम

भोपाल। मध्य प्रदेश के वरिष्ठ आईएएस अधिकारी मोहम्मद सुलेमान ने राज्य शासन से स्वेच्छिक सेवानिवृत्ति (वीआरएस) की मांग की थी, जिसे मंजूरी मिल गई है। उन्होंने 1 माह पहले पत्र लिखकर इसका अनुरोध किया था, जो जुलाई 2025 में सेवा समाप्ति से 5 महीने पहले है। 1989 बैच के वरिष्ठ ड्रूस् अधिकारी मोहम्मद सुलेमान ने 2 मार्च 2025 को अपने वीआरएस लेने का ऐलान किया।

TERI में करेंगे पीएचडी: सूत्र को मिली जानकारी के मुताबिक, मोहम्मद सुलेमान वीआरएस लेने के बाद TERI (The Energy and Resources Insti-tute) नामक दिल्ली के प्रतिष्ठित संस्थान से पीएचडी करेंगे।

कूलिंग ऑफ पीरियड के बाद कर सकते हैं

बहुराष्ट्रीय कंपनी ज्वाँइन

ऐसा माना जा रहा है कि पीएचडी करने के दौरान उनका कूलिंग ऑफ पीरियड गुजर जाएगा और इसके बाद वे किसी बहुराष्ट्रीय कंपनी के साथ ऊंचे पद पर जुड़कर काम कर सकते हैं।

उनकी कार्यकाल की उपलब्धियां

मोहम्मद सुलेमान ने अपने करियर में कई महत्वपूर्ण प्रशासनिक पदों पर काम किया और सरकार के विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन में अहम भूमिका निभाई। उनके योगदान ने राज्य प्रशासन में कई बदलाव किए हैं।



आईएएस के VRS लेने का यह होगा असर

इस फैसले से राज्य प्रशासन में बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि उनके जैसे वरिष्ठ अधिकारी का वीआरएस निर्णय निश्चित रूप से प्रशासनिक कार्यों को प्रभावित करेगा।

शिवराज के रहे हैं विश्वस्त

मोहम्मद सुलेमान, एमपी के पूर्व अपर मुख्य सचिव (एसीएस), ने अपनी करियर की शुरुआत ग्वालियर में असिस्टेंट कलेक्टर के रूप में की थी। इसके बाद वह सिवनी, बालाघाट और इंदौर के कलेक्टर रहे। कोरोना महामारी के दौरान, उन्हें स्वास्थ्य विभाग की अहम जिम्मेदारी दी गई थी। वह पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के विश्वस्त अधिकारी रहे हैं।

कमलनाथ की सरकार में भी मिली थी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी

जब 2018 में कांग्रेस की सरकार बनी और कमलनाथ ने मुख्यमंत्री का पद संभाला, तब भी मोहम्मद सुलेमान को महत्वपूर्ण दायित्व सौंपे गए थे। योजनाओं के क्रियान्वयन में अहम भूमिका निभाई। उनके योगदान ने राज्य प्रशासन में कई उन्हें स्विट्जरलैंड के दौर पर साथ लिया।



हालांकि, लक्ष्य हासिल नहीं हुआ और 7-8ब राजस्व की कमी दर्ज की गई। 10-12ब की बढ़ोतरी हो सके। अन्य शराब की कीमतें पिछले साल की तरह ही रहेंगी। सरकार का अनुमान है कि यह कदम मार्च 2025 तक राजस्व लक्ष्य को पूरा करने में मदद करेगा।

शुल्क हटाकर कीमतें कम की गई हैं, ताकि बिक्री की मात्रा बढ़े और राजस्व में 10-12ब की बढ़ोतरी हो सके। अन्य शराब की कीमतें पिछले साल की तरह ही रहेंगी। सरकार का अनुमान है कि यह कदम मार्च 2025 तक राजस्व लक्ष्य को पूरा करने में मदद करेगा।

सिंधु महिला समिति द्वारा फूड बास्केट वितरण



छिंदवाड़ा। जन जन का रखे ध्यान टीबी मुक्त भारत अभियान 100 दिवसीय निक्षय शिविर अंतर्गत आज सिंधु भवन मोहन नगर छिंदवाड़ा में सिंधु महिला समिति के द्वारा दो क्षय रोगी को फूड बास्केट प्रदाय किया गया। सिंधु महिला समिति के पदाधिकारी रीतू परसवानी , संगीता परसवानी, गरिमा हरवानी, कोमल हरवानी, गीता हरजानी की कार्यक्रम में सफल भागीदारी रही। उक्त कार्यक्रम में जिला क्षय केंद्र से एसटीएस जय अहिरवार टीबीएचवी पूर्णमा परिहार, एवं रानू वर्मा की उपस्थिति रही।

बौद्धगया में हो रहे आंदोलन के समर्थन में पटपड़ा के उपासक बौद्ध



परासिया। छिन्दवाड़ा स्थित डॉ. बाबा साहेब आम्बेडकर की प्रतिमा स्थल पर पटपड़ा वहसील परासिया के उपासक बौद्ध अनुयायी उपस्थित हुए ,जिन्होंने बौद्ध गया विहार में स्थित तथागत बुद्ध से संबंधित बौद्ध विहार बौद्ध गया में हो रहे भिक्षुओं के द्वारा किए जा रहे आंदोलन के समर्थन में जिला स्तर पर हुए प्रदर्शन में सम्मिलित होकर विरोध प्रकट करते हुए ज्ञापन प्रस्तुत किया जिसमें यह माँग की गयी कि विहार में स्थित बौद्धगया में जो सम्राट अशोक के द्वारा जो विहार निर्माण कराया गया उस विहार बौद्धिस्ट को सौंपा जाए। पटपड़ा से ज्ञापन देने मोहन मेश्राम, अनिल निकोसे, ताराचंद मेश्राम, शिव निकोसे, लोकेस अहिरवार एवं बड़ी संख्या में उपासक सम्मिलित हुए।

मुख्यमंत्री का स्वागत



छिंदवाड़ा। भोपाल में किसान मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष दर्शन सिंह चौधरी, कृषक नेता संजय सक्सेना, संदीप रघुवंशी एवं अन्य कृषक नेता मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव प्रदेश अध्यक्ष वी.डी.शर्मा का स्वागत करते हुये।

विद्यार्थियों को सशक्तऔर समृद्ध

भारत के संकल्प से कराया अवगत

छिंदवाड़ा। शासकीय विधि महाविद्यालय छिंदवाड़ा में शनिवार को स्वामी विवेकानंद कैरियर मार्गदर्शन योजना एवं आंतरिक गुणवत्ता मूल्यांकन प्रकोष्ठ के तत्वावधान में जम्मू कश्मीर और भारतीय संविधान पर विशेष व्याख्यान का आयोजन किया गया था। जिसमें विषय विशेषज्ञ के रूप मे डॉ विश्वास कुमार चौहान, प्राध्यापक (विधि) और प्रशासनिक सदस्य मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय



विनियमक आयोग भोपाल को आमंत्रित किया गया था। डॉ विश्वास कुमार चौहान ने विषय विशेषज्ञ के द्वारा जम्मू कश्मीर के इतिहास पर प्रकाश डालते हुए जम्मू कश्मीर के विलय का इतिहास बताया और सशक्त और समृद्ध भारत का 22 फरवरी 1994 के संकल्प से अवगत कराया। जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 के संशोधन के पूर्व एवं पश्चात की स्थिति पर व्याख्या की साथ ही गिरिलतित और बलिस्तान की भौगोलिक, आर्थिक, पर्यावरणीय महत्व को समझाया। कार्यक्रम के पश्चात मुख्य वक्ता द्वारा स्वलिखित पुस्तक स्वाधीनता एवं स्वतंत्रता महाविद्यालय ग्रंथालय को समर्प भेंट की गई। कार्यक्रम के अंत मे मुख्य अतिथि के द्वारा सर्वश्रेष्ठ छात्रा की घोषणा भी की गयी। सर्वश्रेष्ठ छात्रा के रूप मे दिव्या सोनी अंतिम वर्ष की छात्रा को चुना गया। कार्यक्रम का संचालन कार्यक्रम की संयोजक डॉ दमयंती कश्यप द्वारा किया गया। स्वागत व्द्वेधन महाविद्यालय के प्राचार्य डॉ बीके अकोदिया के द्वारा दिया गया। विषय का संक्षिप्त परिचय डॉ खेहा कुमारी के द्वारा दिया गया। कार्यक्रम के अंत मे डॉ कमलाकार मोटघरे ने आभार व्यक्त किया।

सरकार ने खुलेआम लूट का लाइसेंस दे रखा है अपने सरकारी अमले को- कांग्रेस

सिवनी। प्रदेश की भाजपा सरकार ने मध्यप्रदेश को भ्रष्ट प्रदेश बना दिया, कोई भी शासकीय अशासकीय अशासकियों का लुटने आं में मोटी रकम दिये बिना अधिकारी, कर्मचारी आम जनता का सीधा-सीधा काम भी करने को तैयार नहीं है। प्रदेश में आये दिन भ्रष्टाचार के मामले अखबार की सुर्खियों में बने रहते है, बडे स्तर के अधिकारी तो छोड़े तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के लिपिक के यहाँ भी करोड़ो रूपय की सम्पत्ति निकाल रही है यह सब काम सत्ताधारी दल के मंत्रियों, नेताओं और अधिकारी, कर्मचारियों की मिली भागत से हो रहे है और आम जनता इसमें पीस रही है शासन के नियम है कि 3 वर्ष से अधिक कोई भी अधिकारी, कर्मचारी उसी स्थान पर पदस्थ नहीं रह सकते अधिक समय तक एक ही स्थान पर रहने से भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलता है। लेकिन प्रदेश की भाजपा सरकार इन भ्रष्ट अधिकारी, कर्मचारियों को एक ही स्थान पर स्थापित कर यह बताना चाह रही हो कि प्रदेश की जनता को लुटने का लाइसेंस इन्हें प्रदेश की भाजपा सरकार से मिल गया हो। प्रदेश का कोई भी शासकीय, अशासकी विभाग, कार्यालय में बिना रिश्वत लिए आम जनों का काम नहीं हो पाते, पैसा देने के बाद भी अनेक चक्कर लगावाये जातेहै।

स्वच्छता सर्वेक्षण...

सिटिजन फीडबैक कैटेगरी में पहले पायदान पर पहुंचा नगरनिगम महापौर ने जताया जनता का आभार

छिंदवाड़ा। इन दिनों स्वच्छता सर्वेक्षण 2024 की तैयारियां जोरो से चल रही है। बीते दिनों दिशा की बैठक में छिंदवाड़ा पांडुर्णा लोकसभा क्षेत्र के सांसद बंटी विवेक साहू ने सभी जनप्रतिनिधियों एवं अधिकारियों को स्वच्छता सर्वेक्षण के फीडबैक में अपनी भागीदारी देने की अपील की थी। इसके उपरांत नगर निगम छिंदवाड़ा महापौर विक्रम अहके के निर्देश पर निगमायुक्त चंद्रप्रकाश राय द्वारा महाअभियान चलाकर फीडबैक लेने के निर्देश दिए। इसका परिणाम यह हुआ कि सिटीजन फीडबैक कैटेगरी में मध्यप्रदेश की सभी 16 नगर निगमों में छिंदवाड़ा नगर निगम पहले पायदान में पहुंच गया। इस उपलब्धि पर नगर निगम छिंदवाड़ा के महापौर विक्रम अहके ने सांसद बंटी विवेक साहू एवं छिंदवाड़ा शहर की जनता का आभार जताया। इस अवसर पर निगमायुक्त चंद्रप्रकाश राय ने कहा कि सर्वेक्षण पूर्ण होने तक छिंदवाड़ा की जनता के सहयोग एवं अधिक से अधिक सकारात्मक फीडबैक की आवश्यकता होगी।



के उत्तर देना होगा। इन उत्तर के बाद मोबाइल नंबर दर्ज किया जाता है जिसमें वन टाइम पासवर्ड (ओटीपी) प्राप्त होगा। इस ओटीपी को वेबसाइट में दर्ज कर फीडबैक की प्रक्रिया को पूर्ण किया जाता है। मोबाइल के इनबॉक्स में, छ-स्क्रन्सकी ओर से ओटीपी प्राप्त होगा जिसे जनता निभीक होकर वेबसाइट में दर्ज कर सकती है।

शहर की जनता के अधिक से अधिक सकारात्मक फीडबैक से नगर निगम छिंदवाड़ा अव्वल स्थान पर बना रहेगा एवं सर्वेक्षण पूरा होने पर निगम को प्रथम स्थान प्राप्त होगा। स्वच्छता सर्वेक्षण 2024 के लिए नगर निगम का सफाई अमला एवं अन्य मैदानी अमला भी इन दिनों अपना शत प्रतिशत दे रहा है। निगम के अधिकारी एवं कर्मचारी स्वच्छता के लिए तो कार्य कर रहे है इसके साथ ही जनता से स्वच्छता का फीडबैक भी ले रहे है। नगर निगम छिंदवाड़ा क्षेत्र के रहवासी भी शहर के लिए सीधे अपना फीडबैक सीधे दे सकते है। इसके लिए स्वच्छ भारत मिशन की वेबसाईट ओपन करने के बाद में नाम टाइप करना होगा है। इस वेबसाइट में जनता को दस आसान प्रश्नों

मवेशियों से भरी 2 पिकअप पुलिस ने पकड़ी

13 भैसों को क्रूरतापूर्वक भरकर ले जा रहे थे आरोपी, केस दर्ज



छिंदवाड़ा। सिंगोड़ी चौकी पुलिस ने दर रात मवेशियों से भरे 2 पिकअप वाहन पकड़े है। दोनों वाहनों में आरोपियों द्वारा करूरतापूर्वक भरकर मवेशियों को ले जाया जा रहा था। इस दौरान पुलिस ने 13 भैसों सहित 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। दरअसल पकड़ाए तश्कर 13 मवेशियों को भुमका घाटी के जंगल में मवेशी चरा रहे लोगों से खरीदकर नागपुर के कल्लखाने ले जा रहे थे। जानकारी में सिंगोड़ी चौकी प्रभारी पंकज राय ने बताया कि शनिवार देर रात मुखबिर के द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि कुछ व्यक्ति अमरवाड़ा से नागपुर तरफ वाहनों में भैसाँ को अवैध परिवहन कर काटने के लिये नागपुर लेकर जा रहे हैं। सूचना पर रेड कार्यवाही कर पिकअप वाहन क्रं. रूक्क 28-त-4185 से कुल 08 गन भैस एवं छोटा हाथी क्र रूक्क28 त 5030 में परिवहन किये जा रहे कुल 05 नाा कुल 13 भैसों को मुक्त कराया गया। चौकी सिंगोड़ी थाना अमरवाड़ा में आरोपियों के विरुद्ध धारा 11 म.प्र. कृषक पशु परिरक्षण अधि., 11 (घ) पशु करस्ता निवारण अधि, (2) धारा 11 म.प्र. कृषक पशु परिरक्षण अधि., 11 (घ) पशु करस्ता निवारण अधि, (3) 5 बीएएस



प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया ।

महत्वपूर्ण भूमिका -निरीक्षक गनपत सिंह उईके, उ.नि.रामकुमार ठाकुर, सर्जन शरद मालवी, आरक्षक सतीश बघेल, योगेश मालवी, राजपाल बघेल, नीरज बघेल,सुर्योदय बघेल,कन्हैया सनोडिया की सराहनीय भूमिका रही ।

परासिया क्षेत्र में विकास कार्यों की दी सौगात...

सांसद ने विभिन्न कार्यों के लिए स्वीकृत किए 12 लाख 50 हजार

छिन्दवाड़ा। सांसद बंटी विवेक साहू ने परासिया विधानसभा क्षेत्र में विभिन्न निर्माण कार्यों के लिए अपनी सांसद निधि से 12 लाख 50 हजार की स्वीकृति दे दी है। अब जल्द ही यहां पर निर्माण कार्य प्रारंभ किये जायेंगे। सांसद श्री साहू ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की मंशा है कि ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को हर मूलभूत सुविधा उपलब्ध हो। इसी मंशा के अनुसार छिन्दवाड़ा और पांडुर्णा जिले में सांसद निधि के साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के सहयोग से अन्य निधियों से भी विकास कार्य किये जा रहे है। सांसद श्री साहू ने कहा कि छिन्दवाड़ा और पांडुर्णा जिले के विकास में कोई भी कसर नहीं छोड़ी जायेगी। केन्द्र एवं राज्य सरकार की निगाहें छिन्दवाड़ा और पांडुर्णा के विकास पर प्रमुख रूप से लगी हुई है। इसी को परिणाम है कि छिन्दवाड़ा एवं पांडुर्णा जिले में स्वास्थ्य सुविधाओं को देखते हुए सबसे अधिक सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र स्वीकृत किये गये है। वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में सार्वजनिक आयोजनों के लिए बड़ी संख्या में सामुदायिक भवनों की भी स्वीकृति मिली है। भाजपा मंडल अध्यक्ष देवी पाल, सरपंच शीशकुमारी मर्सनकोले, जनपद सदस्य कुबेर सिंह सूर्यवंशी, भाजपा नेत्री ज्योति डेहरिया की अनुरंशा पर सांसद साहू की सांसद निधि से ग्राम हरनभटा में लोहगौरी टेकड़ी में देवस्थान तक जाने के लिए 300 मीटर सी.सी. रोड निर्माण के लिए 10 लाख की स्वीकृति दी गई है। वहीं पंचायत तुमड़ी के ग्राम भोकरई में आदिवासी मोहल्ले में रंगमंच निर्माण के लिए 1 लाख रूपये एवं जनपद पंचायत परासिया के ग्राम मानकादेहीखुर्द में व्यायाम शाला एवं जिम के लिए 1.50 लाख की स्वीकृति प्रदान की गई है। विकास कार्यों के लिए राशि स्वीकृत करने पर सभी जनप्रतिनिधियों एवं क्षेत्र के कार्यकर्ताओं ने सांसद बंटी विवेक साहू का आभार व्यक्त किया है।

नेशनल लोक अदालत का आयोजन 8 मार्च को

छिन्दवाड़ा। जिला न्यायाधीश/सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण छिन्दवाड़ा के 22 जनवरी के पत्रानुसार 08 मार्च को विद्युत अधिनियम 2003 की विभिन्न धाराओं के अंतर्गत लंबित प्रकरणों के निराकरण के लिये जिले के विकासखंड छिन्दवाड़ा, अमरवाड़ा, चौरई, सौसर व जुन्नारदेव विद्युत न्यायालयों में नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जायेगा। म.प्र. शासन उर्जा विभाग के निर्देशों के परिक्रेश्य में मप्र पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा नेशनल लोक अदालत में विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 135 के अंतर्गत लिटिगेशन/प्री-लिटिगेशन के लंबित निम्नदाब श्रेणी के सभी घरेलू, स.पी कृषि, 5 किलोवाट भार तक के गैर घरेलू, 10 अश्व शक्ति भार तक के औद्योगिक उपभोक्ताओं के विशेष न्यायालय में दर्ज एवं प्री-लिटिगेशन के प्रकरणों में छूट प्रदान करने के प्रावधान किये है। कंपनी द्वारा मानवीय विशेष न्यायालय में दर्ज प्रकरणों में आंकलित निम्नलि दायित्व की राशि में 20 प्रतिशत एवं सिविल दायित्व की राशि पर छः माही चक्रवृद्धि दर के अनुसार 16 प्रतिशत प्रतिवर्ष लगने वाले ब्याज की राशि में शत-प्रतिशत छूट नियम एवं शर्तों के तहत प्रदान की जायेगी। प्रकरण न्यायालय में दर्ज न होने की स्थिति (प्री-लिटिगेशन) में आंकलित सिविल दायित्व की राशि पर 30 प्रतिशत एवं सिविल दायित्व की राशि पर लगने वाले छः माही चक्रवृद्धि दर के अनुसार 16 प्रतिशत प्रतिवर्ष लगने वाले ब्याज की राशि में शत-प्रतिशत की छूट नियम एवं शर्तों के तहत प्रदान की जायेगी।

भाजपा सांसद की बदजुबानी के खिलाफ फिल्मी वेशभूषा में बॉलीवुड कलाकारों की नन्हे बच्चों के साथ शिक्षकों ने निभाई अदाकारी

छिन्दवाड़ा। भाजपा सांसद की बदजुबानी ने एक बार फिर साबित कर दिया कि भाजपा के संरक्षण में ही अपराध, माफियाराज व गुंडाराज फलफूल रहा है। भाषा की मर्यादा को लांघते हुए जिन शब्दों का प्रयोग उन्होंने मप्र के पूर्व मुख्यमंत्री, छिन्दवाड़ा के विकास पुरूष माननीय कमलनाथ जी के लिए किए, उससे यह भी साफ हो गया कि शांतिप्रिय जिले की फिजा में अपराध घोलने का काम भाजपा कर रही है। माननीय कमलनाथ जी के द्वारा जिले की विगड़ी कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े किए तो सांसद मिट्टी से निकाले गए भूकृमि की तरह तिलमिला उठे, इसका अर्थ यही हुआ कि वे जिले में वर्दीधारी भाजपा कार्यकर्ता चाहते हैं, जो नियम, कानून व कायदों को तोड़कर मरोड़कर सिर्फ और सिर्फ भाजपा के इशारों पर काम करें। उक्त उद्गार आज कांग्रेस जिलाध्यक्ष विश्वनाथ ओकटे ने जारी प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से व्यक्त किए। कांग्रेस जिलाध्यक्ष श्री ओकटे ने आगे कहा कि हर्द में जिला कांग्रेस आदिवासी विभाग के जिलाध्यक्ष पर जानलेवा हमला होता है, एक आदिवासी नेता पर हमला करने वालों का संरक्षण देने वाली भाषा सांसद के द्वारा बोली

जा रही है, क्योंकि हमलावर सत्ता पक्ष से जुड़े हुए और रेत माफिया है। ऐसा एक नहीं बल्कि अनेकों बार हुआ है। हर्दई पुलिस थाना के ठीक पीछे रेत का अवैध भण्डारण, राजमहल के पीछे अवैध रेत का भण्डारण, भाजपा के लोगों के द्वारा बेखौफ शासकीय भूमि पर अतिक्रमण, जिला मुख्यालय पर एक आदिवासी की जमीन भाजपा नेता द्वारा खरीद ली गई और जमीन मालिक को पता भी नहीं चला। ऐसे अनेक अवैधानिक कार्यों की लगातार लिखित शिकायत करने के बाद भी कोई कार्रवाई रेत माफियाओं व भू माफियाओं के खिलाफ नहीं होना इस बात का प्रमाण है कि जिले में कानून व्यवस्था पूरी तरह चौपट हो चुकी है जिसे सुधारने की नितांत आवश्यकता है, किन्तु भाजपा सांसद के बयान से यह साफ झलक रहा है कि वे गुंडाराज को बढ़ावा देना चाहते हैं जिसकी कांग्रेस घोर निंदा करती है। श्री ओकटे ने जारी प्रेस विज्ञप्ति में आगे कहा कि मप्र के पूर्व मुख्यमंत्री व विभिन्न मंत्रालयों के पूर्व केन्द्रीय मंत्री कमलनाथ ने अपना सम्पूर्ण जीवन छिन्दवाड़ा व पांडुर्ना जिले के विकास में समर्पित कर दिया।

जय अग्रसेन महाराज, जय अग्रवाल समाज... कड़ी मेहनत से कर्म करें भाग्य जरूर साथ देगा: विनोद अग्रवाल



छिंदवाड़ा। अग्रवाल पैलैस का लोकार्पण करते हुए इन्दौर के उद्योगपति विनोद अग्रवाल ने छिंदवाड़ा अग्रवाल समाज को बधाई देते हुए कहा कि यह गौरव की बात है कि अग्रवाल समाज का अपना सर्वसुविधा युक्त मैरिज लॉन है ऐसा लॉन आसपास के शहरों में नहीं होगा। इस भवन में सामाजिक गतिविधियां भी होनी चाहिए । उन्होंने कहा कि कर्म करने के लिए लगातार मेहनत की जरूरत है कर्म करेगो तो भाग्य आपका साथ देगा और सफलताएं आपके कदम चूमेगी। उन्होंने कहा कि हमने अपनी व्यापार यात्रा छिंदवाड़ा से प्रारंभ की उन्होंने अपने परिवार की सफलता के जीवन का वृतांत भी बताया। छिंदवाड़ा अग्रवाल समाज के अध्यक्ष उद्योगपति सुरेश अग्रवाल ने मैरिज लॉन के निर्माण की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने सहयोग दिया है अग्रवाल समाज उनका आभार मानता है उन्होंने विनोद अग्रवाल जी के द्वारा दी गई राशी की सराहना की। जब हम उनके पास गए तो उन्होंने कहा कि आप लिख लीजिये तब सुरेश अग्रवाल ने सोचा कि सामने वाला सीना देना चाहता है और हम चांदी मांग रहे हैं। हमें ही नुकसान होगा इसीलिए हमने विनोद जी पर छोड़ दिया और उन्होंने अग्रवाल समाज को एक करोड़ रूपए दिया। अग्रवाल महिला मंडल की महिलाओं ने आकर्षक सांस्कृतिक कार्यक्रम किया । अग्रवाल पैलैस तीन एकड़ में फैला है जो जिले का अब तक सबसे बड़ा और सर्व सुविधायुक्त भवन है।

कमलनाथ अपने शब्द वापस ले: यादव

छिंदवाड़ा। भाजपा जिलाध्यक्ष शेषराव यादव ने कमलनाथ के द्वारा हर्दई में अपने भाषण के दौरान पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ दिए गए बयान पर रोष व्यक्त करते हुए पुलिस कर्मचारियों से माफी मांगने के लिए कहा। भाजपा जिलाध्यक्ष शेषराव यादव ने कहा कि कमलनाथ जी आप बुजुर्ग होकर उम्र के उस पड़ाव में हैं जब आपको राग, द्वेष और बदले की धमकी वाली भाषा की राजनीति को छोड़कर सहिष्णुता और सहयोग की राजनीति करना चाहिए। श्री यादव ने कहा कि आप हमेशा धमकी देते हैं कि आप बहुत बारीक पीसते हैं। कभी धमकी देते हैं जब में बीजेपी का बिस्त्रा रखते हो। आपके इन्हीं धमकी भरे बयानों से जनता ने आपको इतना बारीक पीस दी कि आप अब कर्मचारियों को धमकी देने लगे है। श्री यादव ने कहा कि आप अधिकारियों कर्मचारियों को अपने इशारों पर नचाना चाहते हैं और ये भाजपा के शासनकाल में हो नहीं पा रहा है इसीलिए भाषणों में खीज निकाल रहे हैं। श्री यादव ने कहा कि कमलनाथ जी ये भाजपा का शासनकाल है जिसमें सभी को बोलने की पूरी स्वतंत्रता है इसीलिए आप खुले मंच से पुलिस अधिकारियों को धमकी दे पा रहे हैं। श्री यादव ने कहा कि आप अपने मुख्यमंत्री काल को याद करें जब विधानसभा उपचुनाव के समय आपके निर्देश पर पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान में केंद्रीय कृषि मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के हेलीकॉप्टर को चौरई से उड़ने से रोक दिया गया था। श्री यादव ने कहा कि कमलनाथ भाजपा कभी बदले की राजनीति नहीं करती। श्री यादव ने कहा कि कमलनाथ द्वारा हर्दई में मंच से पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को दी गई धमकी उनके अवसाद को दर्शा रहा है। भाजपा जिलाध्यक्ष शेषराव यादव ने कहा कि हर पिता अपने बेटे को सफल बनाने के लिए मेहनत करता है और आप भी वही कर रहे हैं लेकिन बेटे में क्या क्षमता है वह पिता को जरूर पता होना चाहिए और उसे वही करने देना चाहिए जो वो करना चाहता है, मेरी आपको सलाह है कि आप भी अपने बेटे को वही करने दें जो वह करना चाहता है और छिंदवाड़ा कांग्रेस में किसी और नेता को आगे आने दें। शेषराव यादव ने कहा कि पुलिस अधिकारियों, कर्मचारियों के खिलाफ दिए गए वक्तव्य पर कमलनाथ को शब्द वापस लेते हुए उनसे माफी मांगनी चाहिए।

आंबेडकरवादी भिक्षुओं का अपमान बर्दास्त नहीं करेंगे



छिंदवाड़ा । सदियों पूर्व सम्राट अशोक द्वारा स्थापित विश्व के बौधों का प्रमुख तीर्थ एवं आस्थास्थल बोधगया स्थित महाबोधि महाविहार पर बौद्धों का नहीं बल्कि हिन्दू ब्राह्मण पुजारियों का कब्जा होना विश्व में कौहल का विषय है। भारत में कहीं पर भी,किसी भी आस्थास्थल में गैर धर्मावलंबियों का कब्जा नहीं है,फिर बौद्ध विहार में हिंदुओं का कब्जा क्यूं ? दरअसल इस विहार में विश्व के सभी प्रमुख राष्ट्रों द्वारा अरबों का दान आता है,उसी को हड़पने के लिए यह सरकार को मौन स्वीकृति से यह साजिशें जारी है। भारतीय बौद्ध महासभा के प्रदेश उपाध्यक्ष रमेश लोखंडे ने बताया कि, महाबोधि विहार मुक्ति हेतु विहार परिसर में शांतिपूर्ण आंदोलनरत भिक्षुओं को बिहार सरकार ने बर्बरता पूर्वक आधी रात को खदेड़,यह अमानवीय कृत्य अम्बेडकरी व बौद्धजन कभी बर्दास्त नहीं कर सकते। जिसके निषेधार्थ छिंदवाड़ा जिले के तमाम अम्बेडकरी व बौद्ध संगठन अम्बेडकर तिराहा पर शांतिपूर्ण तरीके से धरना प्रदर्शन कर रैली के रूप में महामहिम राष्ट्रपति के नाम कलेक्टर छिंदवाड़ा को ज्ञापन सौंपा।

फिल्मी वेशभूषा में बॉलीवुड कलाकारों की नन्हे बच्चों के साथ शिक्षकों ने निभाई अदाकारी



परासिया। क्षेत्र के हैप्पी किड्स पब्लिक स्कूल में मनाया गया दीक्षा आरंभ समारोह (ग्रेजुएशन सेरेमनी 2025) इस पूरे प्रोग्राम में बॉलीवुड की थीम में थियेक नन्हे नन्हे बच्चे एवं शिक्षक गण, समस्त शिक्षकों ने निभाई बॉलीवुड थीम की अदाकारी वहीं पालकों ने मंच में आकर विभिन्न खेलों (गेम्स) में भाग लिया, और विद्यालय व शिक्षकों की तारीफ की कार्यक्रम के मुख्य अतिथि विद्यालय के संचालक अरविंदर सिंघ खंडूजा (रिंपी खंडूजा) अर्शलीन कौर खंडूजा जगजीत

सिंघ खंडूजा (बॉबी खंडूजा) हरजीत कौर खंडूजा, विद्यालय के प्राचार्य गोविंद गोस्वामी उप प्राचार्य शरीलात वार्ड मैम ,समस्त शिक्षक गण एवं पालक गण उपस्थित रहे। पूरे कार्यक्रम का निर्देशन प्री-प्राइमरी एवं प्राइमरी की हेड स्वाति पाल मैडम ने किया विद्यालय में कक्षा 2 के विद्यार्थियों को ग्रेजुएशन गाउन व कैप पहनाकर, सर्टिफिकेट व डिग्री से सम्मानित किया गया। वहीं शिक्षकों ने भी फिल्मी वेशभूषा में बॉलीवुड एक्टरों की अदाकारी निभाई , कार्यक्रम का अविगर एंकर के रूप में कायनात अली मैम द्वारा करीबन 11. 00 बजे से आरंभ किया गया जो कि दीक्षा आरंभ समारोह पिछले कई वर्षों से विद्यालय में आयोजित होता आ रहा है, इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य नन्हे नन्हे बच्चों को किडरगार्टन से शिक्षा पूर्ण कर, दीक्षा आरंभ हेतु कक्षा पहली में प्रवेश कराना होता है द्य जिससे बच्चों का उत्साह कई गुना बढ़ जाता है ।



भोपाल में मार्च महीने में दिन में तेज गर्मी पड़ने के साथ बारिश का ट्रेंड भी है। मौसम विभाग के अनुसार, मार्च महीने में गर्मी के सीजन की शुरुआत हो जाती है। इसके चलते दिन-रात के तापमान में बड़ेतराी होने लगती है। आंकड़ों पर नजर डालें तो 30 मार्च 2021 को अधिकतम तापमान रिकॉर्ड 41 डिग्री पहुंच चुका है। वहीं, 45 साल पहले 9 मार्च 1979 को रात में पारा 6.1 डिग्री दर्ज किया गया था।

वर्ष 2014 से 2023 के बीच दो बार ही अधिकतम तापमान 36 डिग्री के आसपास रह्य। बाकी सालों में पारा 38 से 41 डिग्री सेल्सियस के बीच रहा है।